

विकसित भारत समाचार

वर्ष : 11 | अंक : 201 | गुवाहाटी | शुक्रवार, 21 फरवरी, 2025 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों का भी समान विकास कर रही है सरकार : सीएम

पेज 2

एकत्रित और विकसित असम का निर्माण हमारा सपना है : हिमंत

पेज 3

चिकित्सा मंत्री का दावा : भर्ती से इस वर्ष 75 प्रतिशत पदों को भरेंगे

पेज 5

लक्ष्य का पीछा करने में सचिन से विराट को बेहतर मानते हैं सहवाग पेज 7

1.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर रहेगी नजर : सीएम

गुवाहाटी। मुख्यमंत्री गुरुवार को घोषणा की एडवांटेज असम 2.0 : ढांचा शिखर सम्मेलन से 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को सुरक्षित करने के लिए तैयार है। लोक सेवा भवन में प्रेस को संबोधित करते हुए शर्मा ने विश्वास व्यक्त किया कि 25-26 फरवरी के शिखर सम्मेलन में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आएगा, साथ ही 50,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भी आएंगी, जिन्हें बड़े पैमाने पर केंद्र का समर्थन प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि शिखर सम्मेलन में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि आएगी और इसमें और अधिक का गुंजाइश भी है। बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर, हमें 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान अनुमानों में मुकेश अंबानी और सज्जन जिंदल सहित उद्योग जगत के नेताओं द्वारा की जाने वाली प्रमुख कॉर्पोरेट घोषणाएं शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमें अभी भी नहीं पता कि अंबानी, जिंदल और अन्य लोग क्या घोषणा करेंगे - यह उनका विशेषाधिकार है। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि राज्य सरकार को टिकाऊ विमानन ईंधन, बिजली परियोजनाओं, अस्पतालों, विश्वविद्यालयों और मेडिकल कॉलेजों जैसे क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों (एमओयू) के लिए 1,500 विशिष्ट अनुरोध पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। शर्मा ने यह भी संकेत दिया कि सड़क और पुल परियोजनाओं सहित निजी निवेश प्रस्तावों का स्वागत है, लेकिन राज्य मंत्रिमंडल द्वारा उनकी कड़ी जांच की जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि सभी निवेश वास्तविक हों। इसीलिए हम हर प्रस्ताव पर बारीकी से विचार कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अन्य निवेश शिखर सम्मेलनों के विपरीत, जहां पहले समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और बाद में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया जाता है, असम इसके विपरीत दृष्टिकोण अपनाएगा - जिसमें कैबिनेट प्रत्येक प्रस्ताव की पहले समीक्षा करेगा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट

एडवांटेज
असम 2.0

हिमंत विश्व शर्मा ने कि असम आगामी निवेश और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को सुरक्षित करने के लिए तैयार है। लोक सेवा भवन में प्रेस को संबोधित करते हुए शर्मा ने विश्वास व्यक्त किया कि 25-26 फरवरी के शिखर सम्मेलन में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आएगा, साथ ही 50,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भी आएंगी, जिन्हें बड़े पैमाने पर केंद्र का समर्थन प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि शिखर सम्मेलन में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि आएगी और इसमें और अधिक का गुंजाइश भी है। बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर, हमें 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान अनुमानों में मुकेश अंबानी और सज्जन जिंदल सहित उद्योग जगत के नेताओं द्वारा की जाने वाली प्रमुख कॉर्पोरेट घोषणाएं शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमें अभी भी नहीं पता कि अंबानी, जिंदल और अन्य लोग क्या घोषणा करेंगे - यह उनका विशेषाधिकार है। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि राज्य सरकार को टिकाऊ विमानन ईंधन, बिजली परियोजनाओं, अस्पतालों, विश्वविद्यालयों और मेडिकल कॉलेजों जैसे क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों (एमओयू) के लिए 1,500 विशिष्ट अनुरोध पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। शर्मा ने यह भी संकेत दिया कि सड़क और पुल परियोजनाओं सहित निजी निवेश प्रस्तावों का स्वागत है, लेकिन राज्य मंत्रिमंडल द्वारा उनकी कड़ी जांच की जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि सभी निवेश वास्तविक हों। इसीलिए हम हर प्रस्ताव पर बारीकी से विचार कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अन्य निवेश शिखर सम्मेलनों के विपरीत, जहां पहले समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और बाद में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया जाता है, असम इसके विपरीत दृष्टिकोण अपनाएगा - जिसमें कैबिनेट प्रत्येक प्रस्ताव की पहले समीक्षा करेगा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट



अब तक 18 हजार 575 लोगों ने किया आवेदन

गुवाहाटी (हि.स.)। असम सरकार दो दिवसीय एडवांटेज असम 2.0 एवं चाय जनजाति के प्रसिद्ध झुमुर नृत्य को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने गुरुवार को बताया कि अब तक 18 हजार 575 लोगों ने एडवांटेज असम 2.0 के लिए

असम की पहचान अब सेमीकंडक्टर से जुड़ी है : मुख्यमंत्री

गुवाहाटी। एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन में सिर्फ चार दिन शेष रहने के बीच मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने गुरुवार को आशा व्यक्त की कि असम का आगामी सेमीकंडक्टर प्लांट राज्य में अवसर तलाशने के इच्छुक विदेशी निवेशकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनेगा। दिसपुर स्थित लोक सेवा भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए शर्मा ने असम के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ती वैश्विक रुचि पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में असम की पहचान सेमीकंडक्टर से जुड़ी है।

जब मैंने 2019 में जापान और कोरिया का दौरा किया था, तो हमने सिर्फ 20-25 लोगों के सामने रोड शो को संबोधित किया था। इस साल, परिदृश्य पूरी तरह से अलग था। विदेशी देश सक्रिय रूप से सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और उन्नत चिप-निर्माण सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, और असम एक आशाजनक गंतव्य के रूप में उभर रहा है। शर्मा ने आगे बताया कि जापान से लौटने के तुरंत बाद जापानी राजदूत ने असम की सेमीकंडक्टर इकाई का दौरा किया, जिससे परियोजना में अंतर्राष्ट्रीय रुचि मजबूत हुई। जगरीरोड सेमीकंडक्टर इकाई में

भारत की सबसे बड़ी आउटसोर्सिंग सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट (ओएसएटी) सुविधा स्थापित की जाएगी, जिसकी अनुमानित क्षमता प्रतिदिन 48 मिलियन चिप का उत्पादन करने की है। यदि निर्माण कार्य योजना के अनुसार आगे बढ़ता है, तो इस वर्ष के अंत तक चिप उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। इससे पहले, मुख्यमंत्री ने रिवर्स माइग्रेशन की संभावना पर भी प्रकाश डाला था और कहा था कि वर्तमान में राज्य के बाहर कार्यरत कई असमिया युवाओं ने वापस लौटने और

कांग्रेस सांसद रकिबुल हुसैन पर क्रिकेट बैट से हमला

मुख्यमंत्री ने विशेष सुरक्षा देने की घोषणा की



गंगांव /गुवाहाटी (एजे / हि.स.)। कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन पर गुरुवार गंगांव जिले में अज्ञात लोगों के एक समूह ने क्रिकेट के बल्ले से हमला किया। हालांकि, धुबड़ी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद हुसैन सुरक्षित बच गए। उन्हें उनके निजी सुरक्षा अधिकारियों (पीएसओ) ने बचा लिया। इस बात की जानकारी पुलिस ने दी। बता दें कि यह घटना रूपहीहाट के नतून बाजार में उस समय घटी जब हुसैन पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में भाग लेने के लिए दोपहिया वाहन पर सवार होकर जा रहे थे। तभी उनपर हमला हुआ। हमलावरों में से एक ने मौके से भागने से पहले हुसैन को बल्ले से मारा। शेष आरोपी, जिनके चेहरे काले कपड़े से ढके हुए हैं, सांसद के पीएसओ पर हमला करते हैं, जिससे उनमें से एक ने हवा में चैतावनी के तौर पर गोलियां चलाईं। हमलावर फिर मौके से भाग जाते हैं। हमले के पीछे का कारण तत्काल पता नहीं चल सका है। उधर कांग्रेस ने सुरक्षा चूक की गहन जांच की मांग की है, जबकि पुलिस ने कहा है कि उन्होंने जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता और असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने कहा कि मुख्यमंत्री विधानसभा को कानून-व्यवस्था में कथित सुधार के बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन एक सांसद भी सड़कों पर सुरक्षित नहीं है। एक सांसद पर इस तरह से हमला कैसे हो सकता है, इसकी जांच होनी चाहिए। असम के पुलिस महानिदेशक हरमीत सिंह ने कहा कि

S.S. Traders
Suppliers in : All kinds of Door Fittings Modular Kitchen & Accessories, etc.
D. Neog Path, Near Dona Planet ABC, G.S. Road, Guwahati - 05
97079-99344

सुप्रभात
आसमान की तरफ देखो। हम अकेले नहीं हैं। सारा जहां हमारा दोस्त है और सपने देखने और उन्हें पूरा करने वालों की मदद करता है।
- अब्दुल कलाम

न्यूज गैलरी
अदालत में बम रखे होने की सूचना से अफरा तफरी मची

तिरुवनंतपुरम। कलपेट्टा की एक परिवार अदालत में गुरुवार को बम रखे होने की सूचना से अफरा तफरी मच गई। हालांकि यह जानकारी बाद में अज्ञात शख्स ने पुलिस से बताया कि अदालत में बम रखे

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की गाड़ी को बम से उड़ाने की धमकी

मुंबई (हि.स.)। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की गाड़ी को बम से उड़ाने की धमकी ई-मेल के माध्यम से मिली है। मुंबई पुलिस की टीम इस धमकी भरे ई-मेल भेजने वाले की गहन छानबीन कर रही है। मुंबई पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की गाड़ी को बम से उड़ाने संबंधी धमकी भरा ई-मेल गोरगांव पुलिस स्टेशन में अज्ञात शख्स ने भेजा था। इसकी जानकारी मिलते ही इस

गौरव गोगोई की पत्नी के मामले में बड़ा खुलासा 18 बार भारत आया था पाकिस्तानी अली तौकीर शेख : सीएम शर्मा

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने एक बार फिर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न के पाकिस्तानी नागरिक से जुड़े होने के मामले में बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में पता



अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सीएम शर्मा ने दावा किया कि मामले की प्रारंभिक जानकारी कांग्रेस के लिए बेहद घातक है और असम की राजनीति पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। सीएम ने कहा कि तीन दिन में असम पुलिस की एसआईटी ने जांच के दौरान पाया कि अली तौकीर शेख ने 18 बार भारत का दौरा

दस हजार बगरुंबा नर्तकों के साथ एक और विश्व रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में है राज्य

गुवाहाटी। पिछले साल 11,010 बिहू नर्तकों या नासोनी और होल वादकों या धुलिया द्वारा बिहू नृत्य के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश करने की ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद, असम सरकार अब 2025 के अंत से पहले बोडो पारंपरिक लोक नृत्य-बागुरुंबा के साथ एक और उपलब्धि हासिल करने की कोशिश कर रही है। हालांकि, आयोजन की सही तारीख की घोषणा अभी बाकी है। बोडो समुदाय द्वारा अपने लोक नृत्य को वैश्विक मंच पर लाने का प्रयास राज्य की विविध सांस्कृतिक



मणिपुर : राज्यपाल ने की जनता से अपील, कहा- लूटे गए हथियारों को एक हफ्ते के भीतर लौटाएं, नहीं तो होगी कार्रवाई

इंफाल। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने हिमाचल प्रदेश के लोगों से सात दिनों के भीतर लूटे गए और अवैध रूप से रखे गए हथियारों को स्वेच्छा से सौंपने का आग्रह किया है। राज्यपाल ने आश्वासन दिया कि इस अवधि के दौरान हथियार छोड़ने वालों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि सात दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्यपाल की ओर से जारी बयान



में कहा गया कि शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करने वाली दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण बीजेपीस महीनों से घाटी और

अमेरिका से निकाले प्रवासियों को पनामा ने जंगल में भेजा

पनामा। पनामा ने अमेरिका द्वारा निर्वासित किए गए विभिन्न देशों के उन 98 लोगों को बुधवार को अपने डेरियन प्रांत के जंगल के एक शिखर में स्थानांतरित कर दिया, जिन्होंने अपने देश लौटने से इनकार कर दिया है। एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। इस घटनाक्रम से परिचित पनामा के एक अधिकारी ने अपनी पहचान गोपनीय रखे जाने की शर्त पर बताया कि डेरियन भेजे गए प्रवासियों ने अपने देश वापस जाने से इनकार कर दिया है और उन्हें तब तक वहीं रखा



दरअसल, सोशल मीडिया पर झुझार सिंह और सिसगांसाहिब सेवकजथा नाम के फेसबुक प्रोफाइल में भाजपा नेता के नाम का इस्तेमाल करते हुए लिखा गया कि कीसाधारी हर सिख हिंदू है और उसे हिंदू होने पर गर्व होना चाहिए। दिल्ली में

विदेशियों पर दिए गए अपने ही फैसले को पलट नहीं सकता न्यायाधिकरण : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली /गुवाहाटी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि एक बार जब एक नामित विदेशी न्यायाधिकरण, 25 मार्च, 1971 के बाद राज्य में प्रवेश करने वाले किसी व्यक्ति के अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी होने के असम सरकार के दावे को खारिज कर देता है, तो न्यायाधिकरण अतिरिक्त दस्तावेजों के साथ प्रशासन की नई दलील पर अपने आदेश की समीक्षा नहीं कर सकता है। एक न्यायाधिकरण ने 15 फरवरी, 2018 को मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने के बाद, 2016 में दर्ज एक मामले में फैसला दिया था कि एक रेजिजा खातून



बांग्लादेश से विदेशी नहीं थी, जो 25 मार्च, 1971 को या उसके बाद भारत में प्रवेश किया था। 2012 में एक और मामले दर्ज किया गया था जिसमें उसी व्यक्ति पर बांग्लादेश से विदेशी होने का आरोप लगाया गया था। इस पर 24 दिसंबर, 2019 को सुनवाई हुई और न्यायाधिकरण ने फैसला दिया कि 15 फरवरी के आदेश के बावजूद, उसके पास दस्तावेजों और सामग्रियों और यहां तक कि पहले की कार्यवाही में इसके निष्कर्षों की जांच करने की शक्ति थी। खातून ने इसे गुवाहाटी हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसने खातून

भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता : आरपी सिंह

नई दिल्ली। भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। यह खुलासा भाजपा नेता आरपी सिंह ने आज मीडिया से बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। इस देश की यही खूबसूरती है कि यहां हर धर्म के लोगों को पूरी आजादी है। हर कोई अपनी राय स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके नाम पर जो प्रचार किया जा रहा है वह पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि यह देश सभी धर्मों के लोगों का है। जिसके कारण भारत कभी भी पूर्ण हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। इसके साथ ही



आपको बता दें कि कल भाजपा नेता आरपी सिंह को सिखों ने बालदार हिंदू बताया था। भाजपा नेता ने इस पोस्ट की निंदा की और उनके नाम का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया पर गलत जानकारी साझा करने के लिए दिल्ली की साइबर सेल में शिकायत भी दर्ज कराई है।

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771
86382-00107

MURTI AVAILABLE

Available all kinds of Marble & White Metal Murties, Ganesh Laxmi, Radha Krishna, Bishnu-Laxmi, Hanuman, Maa Durga, Saraswati, Shivaling, Nandi etc. **ARTCLE WORLD, S-29, 2nd Floor, Shoppers Point, Fancy Bazar, Guwahati-01, Ph.: 94350-48866, 94018-06952**

एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए दक्षिण-पूर्व एशिया से संपर्क बढ़ाने का प्रयास

गुवाहाटी (हिंस)। असम विधानसभा में एक्ट ईस्ट पॉलिसी अफेयर्स को लेकर विधायक धर्मेश्वर कोंबर सवालों का जवाब देते हुए मंत्री चंद्रमोहन पटवारी ने बताया कि भारत, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस नीति के अंतर्गत भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय हाईवे, कलादान मल्टी-डोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट और बीबीआईएन मोटर वाहन समझौता जैसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। साथ ही, भारत-आसियान सहयोग को भी उच्चस्तरीय चर्चा के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है।

अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों का भी समान विकास कर रही है सरकार : सीएम

गुवाहाटी (हिंस)। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र का भी समान रूप से विकास कर रही है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज से लेकर बड़े बड़े सड़कों, पुलों आदि का व्यापक पैमाने पर निर्माण किया जा रहा है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री ने ब्रह्मपुत्र नद पर मोरीगांव और नरंग के बीच बनाए जा रहे पुल, जोगीघोषा में ब्रह्मपुत्र नद पर पुल के दोहरीकरण, ब्रह्मपुत्र नद पर धुबड़ी-फुलगुड़ी निर्माणाधीन पुल आदि की चर्चा की। मुख्यमंत्री गुवाहाटी को असम विधानसभा के चालू बजट अधिवेशन के तीसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा का उत्तर दे रहे थे। चर्चा के दौरान विधायक शेरमान अली ने आरोप लगाया कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। राज्य में 40 फीसदी अल्पसंख्यकों की आबादी है, लेकिन अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा, आवागमन आदि की कोई

सुविधा नहीं तैयार की जा रही है। गुवाहाटी से ग्वालापड़ा तक एक भी पुल नहीं है। स्कूलों में शिक्षक और अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं। वहीं, विधायक अमीनुल इस्लाम ने आरोप लगाया कि 52 वर्षों के कांग्रेस शासन काल में अल्पसंख्यकों की उषेधा की गई। भाजपा की सरकार बनने के बाद एक उम्मीद जगी थी, लेकिन अल्पसंख्यक इलाकों का विकास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी इलाकों का सम विकास नहीं करने से असम देश के पांच राज्यों की श्रेणी में नहीं आ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के संरक्षण में सिडिकेट हो रहा है। पुलिस अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में बर्बरता कर रही है। रात को पुलिसवाले लोगों को घर से उठा



हुई है। राज्य सरकार ने बंधक विलेखों पर स्टाम्प शुल्क में कमी और इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर में कटौती करके 148 करोड़ रुपए की कर राहत जनता को दी है। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने कई नई योजनाओं और परियोजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य का बजट पांच स्तंभ सामाजिक सुरक्षा, मानव संसाधन विकास, बुनियादी ढांचे का विकास, हरित विकास और आर्थिक गतिविधियों के विकास पर आधारित है। उन्होंने कहा कि दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलने के लिए हम परियोजनाओं और जन कल्याण योजनाओं को तैयार करने और उन्हें लागू करने का काम कर रहे हैं।

रक्षा में खड़े हुए थे। उदात्तगुड़ी में जब अल्पसंख्यकों पर गोलियां चल रही थीं, उस समय भी डॉ. शर्मा स्वयं उनकी हिफाजत में खड़े थे। इसीलिए इस प्रकार का आरोप लगाया जाना बेबुनियाद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी के साथ वही व्यक्ति सम्मान रूप से खड़ा हो सकता है, जिसके अंदर सनातन संस्कार हो। बीच में विधायक अखिल गोगोई द्वारा मुख्यमंत्री पर चुनाव के करीब आने को लेकर सुर बदलने का आरोप लगाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें किसी अल्पसंख्यक का वोट नहीं चाहिए। वोट मांगने भी नहीं जाएंगे। लेकिन, वह मुख्यमंत्री रहते हुए सबके साथ न्याय करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रम का कारोबार करने वाले, अपराध करने वाले, लव जिहाद करने वाले, बटुवा की जमीन दखल करने वालों के प्रति उन्हें कोई सहानुभूति नहीं है। लेकिन, सभी आम लोगों को समान रूप से उनका अधिकार दिया जा रहा है, चाहे वह अल्पसंख्यक हों।

राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने त्रिवेणी संगम में लगाई डुबकी



अयोध्या। असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने गुरुवार को त्रिवेणी संगम में सपरिवार आस्था की डुबकी लगाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज प्रयागराज महाकृष्ण के दिव्य संगम में अवगाहन का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। मां गंगा से विनम्र प्रार्थना है कि वे समस्त प्रदेशवासियों एवं प्रियजनों पर अपनी कृपा-दृष्टि बनाए रखें, उन्हें सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य एवं आध्यात्मिक उत्कर्ष प्रदान करें। हर-हर गंगो।

गुजरात सरकार ने पेश किया 3.70 लाख करोड़ का बजट

गांधीनगर। गुजरात विधानसभा में गुजरात को वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का 3.70 लाख करोड़ का बजट पेश किया। बजट में राज्य सरकार ने कोई नया कर नहीं लगाया है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मोटर व्हीकल टैक्स में कटौती और बंधक विलेखों पर स्टॉप शुल्क में कमी करके 148 करोड़ की कर राहत दी है। गुजरात विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3,70,250 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। इसमें पिछले साल के मुकाबले 37,785 करोड़ रुपए या 11.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी

हुई है। राज्य सरकार ने बंधक विलेखों पर स्टाम्प शुल्क में कमी और इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर में कटौती करके 148 करोड़ रुपए की कर राहत जनता को दी है। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने कई नई योजनाओं और परियोजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य का बजट पांच स्तंभ सामाजिक सुरक्षा, मानव संसाधन विकास, बुनियादी ढांचे का विकास, हरित विकास और आर्थिक गतिविधियों के विकास पर आधारित है। उन्होंने कहा कि दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलने के लिए हम परियोजनाओं और जन कल्याण योजनाओं को तैयार करने और उन्हें लागू करने का काम कर रहे हैं।

दिल्ली से किया गया एक-एक कमिटमेंट पूरा किया जाएगा : सीएम

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को दिल्ली सचिवालय में औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला। इससे पहले रेखा गुप्ता ने रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ ली। इसके बाद पूरी कैबिनेट के साथ सचिवालय गई। फिर शाम को यमुना आरती में शामिल हुईं। इसके बाद रात को अपनी कैबिनेट के साथ बैठक की। माना जा रहा है कि इस बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने पहला बयान जारी कर कहा कि विकसित दिल्ली का



जो मिशन है उसे पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। इसमें एक दिन भी व्यर्थ नहीं होगा। दिल्ली से किया गया एक-एक कमिटमेंट पूरा किया जाएगा। सूरजों की मांगों को नई भाजपा सरकार को पहली कैबिनेट में सीएजी की रिपोर्ट को पास किया जाएगा, ताकि इसे सदन के पटल पर रखा जा सके। आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान सीएजी की रिपोर्ट को सदन में पेश नहीं किया गया था। इस पर पीएम मोदी ने कहा भी था कि भाजपा की सरकार बनते ही सदन में सबसे पहले सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी।

चैंपियंस ट्रॉफी : कराची में सबसे ऊंची मीनार पर लहराया तिरंगा

कराची। पाकिस्तान की तमाम कोशिशों के बावजूद कराची के स्टेडियम में भारतीय तिरंगा शान से लहरा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए स्टेडियम में सभी भाग लेने वाले देशों के झंडे लगाए गए थे, लेकिन भारत के तिरंगे को लगाने से इनकार किया गया था। हालांकि, बीसीसीआई के कुछ रुख के बाद पीसीबी को झुकना पड़ा और अब पूरे पाकिस्तान के सामने उसकी फजीहत हो रही है। बुधवार को कराची स्टेडियम की सबसे

ऊंची मीनार पर भारतीय तिरंगा लहराता नजर आया। यह वही पाकिस्तान था, जो दावा कर रहा था कि भारत का तिरंगा उसके स्टेडियम में नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अब न सिर्फ पाकिस्तान का स्टेडियम है, बल्कि वहां तिरंगा भी भारत का ही लहरा रहा है। इससे पहले पीसीबी ने यह तर्क दिया था कि जब भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही है, तो उसका झंडा लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन बीसीसीआई की सख्ती के आगे पीसीबी को

एक न चली। पीसीबी ने इस मामले में आईसीसी को बीच में खींचने की कोशिश की लेकिन सच्चाई यह है कि आईसीसी में भी बीसीसीआई तक पहुंचती तो उन्होंने तुरंत कि वह भारत के खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। खुद पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस और विशेषज्ञ मान रहे हैं कि पाकिस्तान की औकात बीसीसीआई के आगे कुछ भी नहीं। पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ,

जिसमें कराची स्टेडियम में सभी टीमों के झंडे तो लगे थे, लेकिन भारत के तिरंगे को जानबूझकर हटाया गया था। जब यह बात बीसीसीआई तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत आईसीसी और पीसीबी पर दबाव बनाया। नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान को झुकना पड़ा और पूरे देश के सामने फजीहत झेलनी पड़ी। पाकिस्तान के कुछ लोगों ने इस मुद्दे पर भारत के ऐतिहासिक स्थलों से तुलना करने की कोशिश की, लेकिन हकीकत यह

है कि भारत की ताकत और वैश्विक स्थिति से पाकिस्तान कोसों दूर है। पाकिस्तान में सुरक्षा हालात इतने खराब हैं कि वहां कोई विदेशी नेता बिना कड़ी सुरक्षा के नहीं आ सकता जबकि भारत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी परिवार समेत बेफिक्री से घूम चुके हैं। इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि जब बावत भारत की प्रतिष्ठा की आती है, तो बीसीसीआई और भारत सरकार किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं।

पृष्ठ एक का शेष

1.50 लाख करोड़ ...

23 फरवरी को गहन जांच करेगी और इसकी मंजूरी के बिना किसी समझौता जापान पर हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम वास्तव में इन निवेशों को सुविधाजनक बना सकें। महत्वपूर्ण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रचने के साथ, एडवांटेज असम 2.0 राज्य के औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम साबित होगा।

अब तक 18 हजार 575 ...

सम्बलन किया है। मुख्यमंत्री ने लोक सेवा भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शुक्रवार से गुवाहाटी में झुमुर का अभ्यास सत्र आयोजित किया जाएगा। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने झुमुर नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। विश्व रिकॉर्ड के लिए झुमुर नृत्य का प्रदर्शन पर होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर झुमुर नृत्य का आनंद लेंगे। सभी विभागों के प्रमुख भी झुमुर नृत्य का आनंद लेंगे। सभी विभागों के प्रमुख 23 फरवरी को काजीरंगा आएंगे तथा सभी 25 फरवरी को एडवांटेज असम में शामिल होंगे। 25 फरवरी को सब वापस लौट जाएंगे। यात्रा का सारा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को झुमुर नृत्य के बाद प्रदर्शनी देखेंगे। एडवांटेज असम के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि असम के उद्योगपति अभिजीत बरुवा अपना पहला भाषण देंगे। एसआरडी समूह के अनुपम डेका भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, टाटा समूह के एन चंद्रशेखरन और सखन जिनंद भी एक भाषण देंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव भी बोलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर, नुमलुगोड बांस उद्योग पर चर्चा की जाएगी। असम की चाय पर भी चर्चा होगी। यह भी चर्चा होगी कि छोटे पैमाने के उद्योगों को कैसे विश्व स्तर पर ले जाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 18 हजार 575 लोगों ने एडवांटेज असम के लिए आवेदन किया है। इसमें से 15,000 आवेदनों को मंजूरी दी गयी है। अब तक 1,512 एमओयू आवेदन प्राप्त हैं। असम के छोटे उद्योगियों को 12 हजार करोड़ रुपए के एमओयू आवेदन दिए हुए हैं। इसमें से 1,517 एमओयू राज्य के बाहर से आए हैं। उन्होंने कहा कि एमओयू पर फैसला 23 फरवरी को मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। प्रदर्शनी को आम जनता के लिए 27, 28 फरवरी और 1 मार्च को खोला जाएगा। झुमुर का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि झुमुर नृत्य का आनंद लेने के लिए प्रवेश पत्र लेना होगा। प्रवेश पत्र श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र, सरसजाई में प्राप्त किया जा सकता है। प्रवेश पत्र सांस्कृतिक निदेशालय में भी उपलब्ध है। 23 फरवरी को झुमुर का अंतिम अभ्यास हर कोई देख सकेगा।

असम की पहचान ...

सेमीकंडक्टर उद्योग में योगदान देने की इच्छा व्यक्त की है। शर्मा ने कहा कि यदि हम अधिक उद्योगों को आकर्षित कर सकें, तो हमारे युवा पर लौट सकते हैं और असम को विकास कहानी का हिस्सा बन सकते हैं। असम ने भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति बना ली है, इसलिए अब सभी की निगाहें 25-26 फरवरी को होने वाले एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन पर टिकी हैं।

कांग्रेस सांसद रिकबुल ...

हुसैन सुरक्षित हैं। उन पर भीड़ ने हमला किया था। उनके सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें बचाया। हालांकि, हमले में दो सुरक्षाकर्मियों घायल हो गए। पिछले साल धुबड़ी लोकसभा सीट से हुसैन ने रिकॉर्ड 10 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। उनके बेटे ने समागुरी विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव लड़ा था, जिसका प्रतिनिधित्व हुसैन ने पांच बार किया था, लेकिन वे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिव्य रंजन शर्मा से हार गए थे। पिछले वर्ष नवंबर में उपचुनाव के दौरान इस निर्वाचन क्षेत्र तथा अस-पास के क्षेत्रों में हिंसा की

कई घटनाएँ दर्ज की गयी थीं। उधर कांग्रेस सांसद रिकबुल हुसैन पर उनके खुद के क्षेत्र में हुए हमले के बाद मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में उनके कुछ क्षेत्र में उन पर हमलों की घटनाएँ बढ़ने के कारण यह फैसला लिया गया है कि जब भी रिकबुल सामागुरी जाएंगे, उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा दी जाएगी। विधानसभा के चालू बजट सत्र के तीसरे दिन गुरुवार को राज्यपाल का अभिभाषण पर हुई चर्चा का उत्तर देने के बाद मुख्यमंत्री ने सांसद रिकबुल के सुरक्षा से संबंधित बात कही। सदन के कार्यवाही के बीच में कांग्रेस विधायक बाजेद अली चौधरी ने सदन को कांग्रेस सांसद पर हुए हमले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री से इस पर बयान देने की मांग की थी। वहीं, असम के पुलिस महानिदेशक हरमीत सिंह ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि रिकबुल के दो पीएसओ (सुरक्षा अधिकारी) को हल्की चोटें आई हैं और फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

18 बार भारत आया...

किया था। हम यह पता चल जाएगा कि उसे किसने बुलाया था और रोकना था। प्रारंभिक जांच में जो चीजें बताने वाले तथ्य सामने आए हैं इसका असम की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी में जो तथ्य सामने आए हैं वे कांग्रेस के लिए बेहद घातक हैं। मैं एक विधानसभा में एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में यह कह रहा हूँ। मैं असम विधानसभा से वादा करता हूँ कि हम अली शेष के नेटवर्क को तोड़ देंगे। हमें तीन महीने का वक्त दें। हम अगस्त के सत्र में सब कुछ बताएंगे। जांच के नतीजे कुछ लोगों के लिए परेशानी बन सकते हैं। सीएम ने कहा कि शेष जलवायु कार्रवाई समूह में काम करता था, लेकिन उसके ट्वीट और सोशल मीडिया गतिविधियाँ असम के प्रवासियों पर केंद्रित थीं। यह भारत के अतिरिक्त मामलों में दखल देने की कोशिश है। असम के सीएम और भाजपा ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ पर पाकिस्तान आरोप उसकी बदनाम खूफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध रखने का गंभीर आरोप लगाया है। असम पुलिस ने सोमवार को पाकिस्तान के नागरिक अली तौकीर शेष के खिलाफ एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की थी, जो असम और भारत के अतिरिक्त मामलों पर सोशल मीडिया पर डिप्टिगियां कर रहा था। अली तौकीर शेष, जो पाकिस्तान योजना आयोग के सलाहकार हैं और एलिजाबेथ कॉलबर्न के पूर्व सहकर्मी भी हैं, के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। असम कैबिनेट ने रविवार को फैसला लिया था कि गोगोई और उनकी ब्रिटिश पत्नी के खिलाफ कोई मामला नहीं दर्ज किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के नागरिक अली तौकीर शेष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया। सीएम शर्मा ने रविवार को नरम रुख अपनाते हुए कहा था कि गौरव गोगोई को बड़े एंटी-इंडिया साजिश में फंसाया या ब्लैकमेल किया जा सकता है और इसके लिए उन्होंने उनके लिए सहानुभूति व्यक्त की थी। सीएम ने कहा था कि सरकार केंद्र से इस बात की जांच करने का अनुरोध करेगी कि ब्रिटिश नागरिक होते हुए भी एलिजाबेथ कोलबर्न ने लोकसभा चुनावों में प्रचार किया था या नहीं। उन्होंने कहा था कि मैंने देश की सुरक्षा और संप्रभुता को रक्षा करने की शपथ ली है और इसे किसी भी हालत में बनाए रखूंगा। यह राजनीति या व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर है, यह हमारे देश की बात है। गौरवलब है कि गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ गोगोई इन दिनों विवाद में हैं। दरअसल सीएम हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता एलिजाबेथ गोगोई की विदेशी नागरिकता पर सवाल उठा रहे हैं और उनके पाकिस्तानी खूफिया एजेंसी आईएसआई से लिंक होने का आरोप लगा रहे हैं। भाजपा ने गौरव गोगोई के भी साल 2015 में पाकिस्तान के तत्कालीन उच्चायुक्त से मिलने पर भी सवाल उठाए। हालांकि गौरव गोगोई ने सीएम के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि सीएम अपने

ऊपर लगे आरोपों से ध्यान बंटाने के लिए उन पर और उनके परिवार पर आरोप लगा रहे हैं।

ऑस्ट्रेलिया ने अपने ...

ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने मिशन प्रमुखों को राज्य में लाने के लिए एक विशेष विमान की व्यवस्था की है और इसका खर्च विदेश मंत्रालय वहन करेगा। उन्होंने कहा कि पीएमओ और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेशी दूतों के प्रतिनिधिमंडल की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए विशेष पहल की है। उन्होंने कहा कि पांच देशों - सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, भूटान और जापान - के एक उच्च स्तरीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने शिखर सम्मेलन में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है, जबकि मलेशिया भी इसमें शामिल हो सकता है। सीएम शर्मा ने कहा कि शिखर सम्मेलन से पहले इन देशों में रोड शो आयोजित करने से लाभ मिला है।

दस हजार बगरुंबा ...

विरासत को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। 10,000 नर्तकों की अपेक्षित भागीदारी के साथ, यह भव्य आयोजन न केवल रिकॉर्ड तोड़ेगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर असम की समृद्ध परंपराओं को भी उजागर करेगा। बगरुंबा बोडो समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जो असम के स्वदेशी समूहों में से एक है। यह नृत्य शैली बोडो लोगों की सांस्कृतिक पहचान में गहराई से समाहित है और प्रकृति, सद्भाव और आध्यात्मिकता के उत्सव के रूप में कार्य करती है। मातृमू हों कि *बगरुंबा* शब्द दो बोडो शब्दों से उत्पन्न हुआ है: *बागु* जिसका अर्थ है पक्षी और *रुंबा* जिसका अर्थ है नृत्य। इसका अनुवाद *पक्षियों का नृत्य* है, जो कलाकारों की तरल और सुंदर हरकतों को पूरी तरह से दर्शाता है। अक्सर *तितली नृत्य* के रूप में संदर्भित, बगरुंबा तितली के पंखों की जानुजक झड़झट और उड़ान में पक्षियों की कोमल हरकतों को दर्शाता है।

लूटे गए हथियारों ...

पहाड़ी दोनों में मणिपुर के लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी समुदायों को शत्रुता को समाप्त करने और समाज में शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगे आना चाहिए, ताकि लोग अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में लौट सकें। इसको लेकर मैं ईमानदारी से सभी समुदायों के लोगों, खासकर घाटी और पहाड़ी के युवाओं से आग्रह करता हूँ कि वे स्वेच्छा से आगे आएँ और लूटे गए और अवैध रूप से रखे गए हथियारों, गोला-बारूद को नजदीकी थानों/चौकियों या सुरक्षा बलों के शिविर में आज से अगले सात दिनों के भीतर सौंप दें। राज्यपाल ने कहा कि हथियार लौटाने का यह कदम शांति कायम रखने के लिए एक प्रभावी कदम हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैं आपको आश्चर्य करता हूँ कि अगर ऐसे हथियार तय समय के भीतर वापस कर दिए गए, तो कोई दंडात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। इसके बाद ऐसे हथियार रखने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एन. बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पूर्वोत्तर राज्य में अनिश्चितता बनी हुई थी। इसके बाद केंद्र ने 13 फरवरी को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, मणिपुर विधानसभा को भंग कर दिया गया है, जिसका कार्यकाल 2027 तक है।

अमेरिका से निकाले ...

जाएगा जब तक कि उन्हें लेने के लिए कोई तीसरा देश आगे नहीं आता। ये 98 लोग अमेरिका सरकार द्वारा पनामा भेजे गए 299 प्रवासियों के एक बड़े समूह का हिस्सा हैं। अन्य लोग पनामा सिटी के एक होटल में पुलिस की निगरानी में हैं और उन्हें उनके देश वापस भेजने की व्यवस्था की जा रही है। पनामा सरकार ने इस बात से इनकार किया है कि इन लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन वे पुलिस की निगरानी में हैं और उन्हें होटल से बाहर

जाने की अनुमति नहीं है। पनामा की राष्ट्रीय आव्रजन सेवा ने बुधवार को पहले घोषणा की थी कि एक चीनी महिला होटल से भाग निकली थी, लेकिन बाद में अधिकारियों ने बताया कि उसे पुनः पकड़ लिया गया है। पनामा के सुरक्षा मंत्री फ्रैंक अन्ब्रेगो ने मंगलवार को कहा था कि पनामा और अमेरिका के बीच प्रवास समझौते के तहत प्रवासियों को चिकित्सकीय देखभाल और भोजन मुहैया कराया जा रहा है।

विदेशियों पर दिए ...

को विदेशी नहीं घोषित करने के पहले के फैसले के बावजूद टिब्बनल के इस सवाल पर नए सिरे से विचार करने के अधिकार को बरकरार रखा। खातून की ओर से पेश बरिष्ठ अधिवक्ता पीयूष राय ने जस्टिस एसओका और उज्ज्वल भुयान की पीठ को बताया कि टिब्बनल के पास अपने स्वयं के आदेशों की समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है। दलील को स्वीकार करते हुए पीठ ने कहा कि राज्य सरकार 2018 के आदेश में एक पक्ष थी और उसने न तो आदेश को वापस लेने की मांग की और न ही इसे हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी। पीठ ने कहा कि (दिसंबर 2019) का आदेश संकेत देता है कि न्यायाधिकरण अपने स्वयं के निष्कर्षित निर्णय और आदेश के खिलाफ अपील में बैठना चाहता है। न्यायाधिकरण द्वारा ऐसी शक्ति का प्रयोग कभी नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार या उस मामले के लिए केंद्र सरकार का उपाय 15 फरवरी, 2018 के आदेश को चुनौती देना था कि पीठ ने कहा कि न्यायाधिकरण अपने स्वयं के आदेशों पर पुनर्विचार करने और उच्च न्यायालय के आदेश के साथ-साथ न्यायाधिकरण के 24 दिसंबर, 2019 के फैसले को रद्द करने के लिए शक्तिहीन है। इसके अलावा, पीठ ने केंद्र या असम सरकार को न्यायाधिकरण के 2018 के आदेश को चुनौती देने से रोक दिया।

भारत कभी भी ...

जीत के बाद अब भाजपा को भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। हमारा संकल्प है कि भारत हिंदू राष्ट्र था और रहेगा। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस पोस्ट के बाद जहां आरपी सिंह ने खुद को इस बयान से अलग कर दिया, वहीं उनके खिलाफ दिल्ली साइबर सेल में गलत और भ्रामक सूचना फैलाने की शिकायत भी दर्ज कराई गई है। शिकायत में उन्होंने इन सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में जानकारी साझा की और कहा कि ये उनकी ख़िन्न खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही। आपको बता दें कि कल एक हिंदी चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी यही बयान दिया था कि भाजपा भारत में हिंदू राष्ट्र नहीं देखती है।

अदालत में बम...

जाने का दावा करने वाला संदेश अदालत के आधिकारिक ईमेल पर प्राप्त हुआ था। अदालत के कर्मचारियों ने इसकी जानकारी तुरंत न्यायाधीश को दी, जिन्होंने बरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सूचित किया। इसके बाद, निरीक्षण के लिए बम निरोधक दस्ते और स्वान दस्ते को तैनात किया गया। हालांकि, पुलिस ने बताया कि गहन तलाशी में एक बड़े कोर्ड विस्फोटक नहीं मिला। पुलिस को दोपहर करीब 12.30 बजे सूचना मिली और उसने तुरंत कार्रवाई की।

डिप्टी सीएम एकनाथ ...

ई-मेल को भेजने वाले के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इसी तरह का ई-मेल आज फिर से मंत्रालय और जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन में भी आया है। इसलिए इस तरह का ई-मेल भेजने वालों की खानबीन की जा रही है। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे की सुरक्षा की समीक्षा की गई है। इससे पहले जनवरी में एक 24 साल के युवक ने सोशल मीडिया पर एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी दी थी। इस घटना के बाद राणे के श्रीनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।

APOLLO HOSPITALS CHENNAI
ANDROLOGIST & MALE INFERTILITY
Dr. Vilvapathy S. Karthikeyan MS, MRCS(Ed), MCh(Uro), FJRS
WILL BE AVAILABLE FOR CONSULTATION AT GUWAHATI
ON 28th February 2025
Patients suffering from Erectile dysfunction, Premature ejaculation, Low sperm count, Azospermia, Varicocele, Long Standing Testis pain, Pain after ejaculation, Thin stream of urine, Blood in semen, Semen in urine, infections in semen, Thin semen etc may register their names in advance at:
APOLLO HOSPITALS REGIONAL OFFICE
Rajgarh Main Road, Opp-By Lane -10
Ph : 8404037649, 03613102669, 0361-3102166

तापमान	अधिकतम	न्यूनतम
	28°	14°

एकत्रित और विकसित असम का निर्माण हमारा सपना है : हिमंत

गुवाहाटी (हिस)। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि एक एकत्रित और विकसित असम के निर्माण का उनका सपना है और इसी को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोकराझाड़ में असम विधानसभा का पहला अधिवेशन बुलाने का उनका यही मकसद था कि बोडोलैंड के लोग इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकें कि उन्हें शासन का पूरा अधिकार मिल गया है। मुख्यमंत्री गुरुवार को असम विधानसभा के चालू बजट सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा का उत्तर दे रहे थे। प्रतिपक्ष के तत्वाधीन विधायक देवव्रत सैकिया ने सदन में सवाल उठाया कि सरकार यदि कोकराझाड़ में विधानसभा का अधिवेशन कर सकती है तो शिवसागर में क्यों नहीं। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवसागर के लोग कभी भी पुष्कल असम की मांग नहीं करते हैं। लेकिन, बोडोलैंड क्षेत्र में शुरू से ही डिवाइड असम 50-50 की मांग को लेकर शांतिपूर्ण तथा हिंसक दोनों ही प्रकार के आंदोलन होते रहे थे। मुख्यमंत्री दिवेंदर सैकिया से लेकर सर्वोच्च सोनोवाल तक किसी भी मुख्यमंत्री ने बोडोलैंड क्षेत्र में चार कोई कार्यक्रम करने की हिम्मत नहीं की। 2019 में बोडोलैंड एकाईड के समय सशस्त्र आंदोलन कर रहे

एनडीएफबी तथा अहिंसक आंदोलन कर रहे आल बोडो स्टूडेंट यूनिनियन ने डिवाइड असम 50-50 की मांग छोड़कर एकत्रित असम की बात इस शर्त पर स्वीकार की कि एकत्रित असम में रहकर उनका पृथक शासन चाहिए। यही वजह है कि कोकराझाड़ में विधानसभा का अधिवेशन आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम तब तक एकत्रित रहेगा और विकसित होता रहेगा जब तक जनजातियों को शासन का समान अधिकार दिया जाता रहेगा। चाहे वह कार्बी आंग्लोंग हो या बोडोलैंड राभा हाजोंग या फिर अन्य कोई जनजातीय काउंसिल- यह सरकार सभ्य को शासन का समान अधिकार दे रही है। विधायक अखिल गोगोई तथा अन्य कई विपक्षी विधायकों द्वारा असम को अन्य राज्यों की तुलना में पीछे दिखाने संबंधी प्रस्ताव किए गए आंकड़ों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के दिनों में इन सभी आंकड़ों का ग्राफ ऊंचा हुआ है। आजादी के समय असम की अर्थव्यवस्था पूरे देश की अर्थव्यवस्था से मजबूत थी। लेकिन, भाषा को लेकर हुए आंदोलन से लेकर तमाम आंदोलनों के कारण असम की अर्थव्यवस्था धराशायी होती गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 तक असम की जीडीपी को पंजाब से ऊपर ले जाने का उनका प्रयास है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती

सरकारों के दोनों की विफलता का श्रेय भी उनकी सरकार को नहीं दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समय असम के स्वर्णिम सपनों के पूरा होने का है। चाहे वह चराईदेव मैदान को विश्व धरोहर की स्वीकृति मिलने की बात हो या फिर लांचित बरफुकन को लेकर सरकार को उपलब्धियों- सरकार के लिए आठ करोड़ रुपए प्रति स्कूल दिए जा रहे हैं। चाय बागानों में 280 नए स्कूल खोले गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम सरकार केंद्र सरकार द्वारा धान और सरसों पर दिए जा रहे न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त भी एक राशि किसानों को देगी। उन्होंने कहा कि मक्का की भी एमएसपी के दायरे में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से अपील की कि इस वर्ष को एच ऑफ द बुक के रूप में मनाए। राज्य के हर चपे-चपे पर लाइव्री खोलने की सरकार की योजना है। आज की इस चर्चा में सत्ता तथा प्रतिपक्ष के कई विधायकों ने हिस्सा लिया। विधायक गुणा दास बोडो ने कहा कि सरकार जहां भी नए कॉलेज खोल रही है वहां इस बात का ध्यान दे कि उच्चतर

माध्यमिक विद्यालय है या नहीं। जबकि, भाजपा विधायक दिप्लू रंजन शर्मा ने कहा कि सबका साथ सबका विकास का सबसे बड़ा उदाहरण सामगुरी क्षेत्र है। वहीं, कांग्रेस विधायक कमलाक्ष दे पुरकायस्थ ने कहा कि इस सरकार ने चार वर्षों में जितना काम किया है पहले कभी इतना काम नहीं हुआ। जबकि, भाजपा विधायक हेमांग ठाकुरिया ने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं की चर्चा की। विपक्षी विधायक अखिल गोगोई ने कहा कि सरकार ने बोडोलैंड क्षेत्र में विधानसभा का अधिवेशन तो बुलाया, लेकिन बिटीआर क्षेत्र के विकास का कोई स्पष्ट रोड मैप राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं दिखाया। वहीं कांग्रेस विधायक का शिवाभिषण बोरा ने कहा कि सरकार निकृष्ट राजनीति कर रही है। जहां सत्ता पक्ष के विधायकों वाले क्षेत्र में अधिक पूंजी का आवंटन हो रहा है, वहीं विपक्षी विधायकों के क्षेत्र में यह नागण्य है। विधायक गणेश कुमार लिंबू ने कहा कि उग्रवाद के कारण चौपट अर्थव्यवस्था आज शांति के कारण फिर से पट्टी पर लौट रही है। उन्होंने सेमीकंडक्टर पॉलिसी तथा सरकार के अन्य उद्यमियों की चर्चा की। वहीं, कांग्रेस विधायक मिसबाहुल इस्लाम लखर ने कहा कि बराक घाटी के विधायक निराश हैं। बराक

घाटी में एकमात्र जो काम हुआ वह करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि रखा गया। इसके अलावा कोई भी कार्य नहीं हुआ। चर्चा काफी लंबी होने के कारण सत्ता तथा प्रतिपक्ष के कई विधायकों को अपनी बातें रखने का मौका नहीं मिला। अंत में मुख्यमंत्री ने बताया कि बिप्लव शर्मा कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा करने से पूर्ववर्ती तरुण गोगोई सरकार के दिनों में सरकारी नौकरियों में हुई धांधली का पोल खुलती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद ने तीन लाख रुपए का सोना उपहार लिया था, वह भी सरेआम हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उमंगशु कोल माइन, सिंडिकेट, बिप्लव शर्मा आयोग की रिपोर्ट आदि मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार एक ही दिन सदन के पटल पर बिप्लव शर्मा की रिपोर्ट और उनके कार्यकाल में दी गई एक लाख 13 हजार नौकरियों की सूची रखेंगे, ताकि लोग देखें कि एक तरफ नौकरी में भ्रष्टाचार और एक तरफ भ्रष्टाचार मुक्त इतने लोगों को दी गई नौकरी। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा स्वच्छ तरीके से दी गई नौकरियां असम के इतिहास में दर्ज रहेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पाकिस्तानी अली तौकीर शेख की गतिविधि को लेकर गठित की गई एसआईटी की जांच में यह खुलासा हुआ है कि तौकीर शेख बार-बार भारत में आता रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने ए फॉर एपल को किया ए फॉर असम : मुख्यमंत्री शर्मा



गुवाहाटी (हिस)। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ए फॉर एपल को बदलकर ए फॉर असम कर दिया है। यानी प्रधानमंत्री ने देश में असम को उन्होंने पहले स्थान पर रखा है। जब यूनेस्को धरोहर के नामांकन की बात आई तो बनारस के मंदिर की जगह असम के चराईदेव का नाम प्रधानमंत्री ने यूनेस्को के लिए भेजा, क्योंकि एक बार में एक देश से एक ही नाम का नामांकन हो सकता था। उन्होंने कहा कि आज जब एडवॉटिज असम 2.0 का समय आया है, तब प्रधानमंत्री ने 51 देश के प्रतिनिधियों को असम भेजने के लिए विशेष विमान की व्यवस्था करने को केंद्रीय विदेशमंत्री एस जयशंकर से कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री देश की गिनती असम से शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री आज असम विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा का उत्तर दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में ब्रह्मपुत्र पर एक के बाद एक पुल से लेकर विभिन्न प्रकार की बड़ी-बड़ी केंद्रीय योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लागू की गईं। एडवॉटिज असम 1.0 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा असम में भारी निवेश किया गया। नामरूप खाद कारखाना को लेकर विभिन्न प्रकार की बातें हो रही थीं, लेकिन प्रधानमंत्री ने केंद्रीय बजट में इसको बढ़े पैमाने पर शुरू करने की मंजूरी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि किस प्रकार नरेंद्र मोदी की सरकार के समय में असम का कायाकल्प हो रहा है।

नगांव जिला उपायुक्त को असम के शहीद स्वतंत्रता सेनानी पुस्तक भेंट की गई



नगांव, नगांव जिला आयुक्त नरेंद्र कुमार शाह से आज 1942 के शहीद परिवार कल्याण समिति के कार्यकारी अध्यक्ष मृणाल कुमार बोरा ने मुलाकात की। इस दौरान श्री बोरा ने नगांव जिला आयुक्त नरेंद्र कुमार शाह को सौमित्र की लिच्छि पुस्तक 'असम के शहीद स्वतंत्रता सेनानी' भेंट की तथा लेखक की प्रचेष्टा की सराहना की। जिला आयुक्त महोदय ने पुस्तक के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाई तथा श्री बोरा को धन्यवाद दिया। मालूम हो कि इस दौरान श्री बोरा के साथ शहीद स्वतंत्रता सेनानी हेमराम बरा के नाती की बहू कस्तुरी अधिकारी भी उपस्थित थीं। उल्लेखनीय है कि मृणाल कुमार बोरा शहीद स्वतंत्रता सेनानी ठगी सूत के नाती हैं।

बरपेटा : सड़क हादसे में एक भूतानी नागरिक की मौत, दूसरा घायल

बरपेटा (हिस)। बरपेटा जिलांतर्गत सरभोग में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए भयावह सड़क हादसे में एक भूतानी नागरिक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृत भूतानी नागरिक चार चक्का वाहन (बीपी-2बी-6878 का चालक बताया गया है। सरभोग पुलिस ने आज बताया है कि मृत चालक और घायल व्यक्ति की पहचान स्पष्ट नहीं हो पाई है। दुर्घटना राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर सरभोग के बरगांव में हुई। हादसा आज तड़के होने की पुलिस ने जानकारी दी है। प्रत्यक्षियों के अनुसार, भूतानी का वाहन (बीपी-2बी-6875) बरपेटा से बंगाईगंवा की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग 27 से होकर जा रहा था। तेज गति से चल रहा भूटिया वाहन अचानक नियंत्रण खो बैठा और डिवाइडर से टकराने के बाद गुवाहाटी की ओर जाने वाले 18 चक्का ट्रक (यूपी-93बीटी-5120) से टकरा गया। हादसे में भूतानी चालक की मौत के पर ही मौत हो गई और उसके सहयोगी को गंभीर चोटें आईं। सूचना मिलते ही मौत पर सरभोग पुलिस पहुंची और मृत चालक को पोस्टमार्टम के लिए बरपेटा मेडिकल कालेज एंड अस्पताल में भेजा।

नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

दक्षिण सालमारा (हिस)। दक्षिण सालमारा मानकाचर जिलांतर्गत मानकाचर में नाबालिग छात्र के साथ दुष्कर्म के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि, दूसरा आरोपी अभी भी फरार बताया गया है। गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान रियाजुल हक (28) के रूप में हुई है। आरोपी को मानकाचर की खरुवाबांधा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार नाबालिग लड़की के साथ बीते 15 फरवरी की रात को दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। उसे मेघालय के फूलबाड़ी इलाके में वाहन से ले जाकर छोड़ दिया गया था। किसी तरह से लड़की ने अपने घर पहुंचकर सारी बात अपने परिवारों को बताई।

रुपहीहाट में ड्रग्स समेत तस्कर गिरफ्तार

नगांव (हिस)। नगांव जिले में रुपहीहाट पुलिस द्वारा लगातार ड्रग्स विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक अभियान चलाते हुए ड्रग्स से भरी प्लास्टिक की साबुनदानी के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने आज बताया है कि रुपहीहाट पुलिस ने रौमारी निवासी साजिद इकबाल के घर पर गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारा और ड्रग्स से भरी साबुनदानी को बरामद करने के साथ ही तस्कर साजिद इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार ड्रग्स तस्कर साजिद इकबाल से बरामद ड्रग्स का वजन 9.30 ग्राम है। पुलिस वर्तमान में अधिक जानकारी के लिए पूछताछ कर रही है।

रंगिया : यौन उत्पीड़न के मामले में एक गिरफ्तार

रंगिया (विभास)। रंगिया थाने में दर्ज शिकायत के आधार पर रंगिया पुलिस ने यौन उत्पीड़न के मामले में रमजान अली नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता ने रंगिया थाने में एक लिखित एफआईआर दर्ज कराई जिसमें कहा गया कि उसकी 7 साल की नाबालिग बेटी के साथ आरोपी व्यक्ति ने यौन उत्पीड़न किया। इस संदर्भ में रंगिया थाने में 42/25 यूएस 65(2)/62 बीएनएस आरडब्ल्यू संस्करण पोस्को एक्ट, 2012 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बताया गया है कि अभियुक्त रमजान अली रंगिया के वार्ड नंबर 1, शरीयतपुर का निवासी है। रंगिया थाने में शिकायतकर्ता, पीड़िता और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद नाबालिग



पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए जीएमसीएच भेजा गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही के लिए न्यायालय भेजा गया है।

विश्वनाथ में जिला विवाह समिति के सौजन्य में सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न



विश्वनाथ (विभास)। राज्य के जिला विश्वनाथ में सामूहिक विवाह संस्कार के द्वारा 18 फरवरी (मंगलवार) को 204 जोड़े विवाह के बंधन में बंध गए। वैदिक रीति-रिवाज व नाम कीर्तन अनुष्ठान के साथ 204 जोड़े जीवनभर के लिए एक-दूसरे के हो गए। उत्तर पूर्वांचल लोक कल्याण समिति, जनकल्याण संस्थान जयपुर, धर्म जागरण समन्वय और विश्वनाथ जिला विवाह समिति के सौजन्य में विश्वनाथ चारिआल के कमलाकांत क्षेत्र वार्किंग जौन में सामूहिक विवाह संस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया। विश्वनाथ, बिहाली, गोहपुर, नदुवार और जिले के अन्य हिस्सों से 204 जोड़े ऐसे हैं जो विभिन्न कारणों से विवाह संस्कार से वंचित रह गए हैं जिसे सामाजिक विवाह कराया गया। विवाहिक जोड़े को उपाहार और वृक्ष भी प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में विश्वनाथ विधायक प्रमोद बरठाकुर, बिहाली विधायक दिगंत घटवाल, विधायक उपलव बरा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी, उत्तर पूर्वांचल लोक कल्याण समिति, जन कल्याण संस्थान, जयपुर, धर्म जागरण समन्वय और विश्वनाथ जिला विवाह समिति के पदाधिकारी, सभी जिम्मेदार कार्यकर्ता और जोड़ों के परिवारों के साथ-साथ हजारों लोग शामिल हुए। उल्लेखनीय है विश्वनाथ में विवाह संस्कार ने विश्वनाथ को एक विशेष आयाम दिया।

आगजनी की दो अलग-अलग घटनाओं में महिला झुलसी और दो दुकान जलकर राख

कामरूप/शिवसागर (हिस)। कामरूप (ग्रामीण) एवं शिवसागर जिलों में दो अलग-अलग आग लगने की घटनाओं में एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जबकि दो दुकानें जलकर राख हो गईं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आज तड़के कामरूप (ग्रामीण) जिला के रंगिया नगर में एक घर में आग लग गई। इस घटना में घर में सो रही मोइना जय गंधीर रूप से झुलस गई। वहीं आग लगने से घर की सारी संपत्ति जलकर राख हो गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी ओर शिवसागर जिलांतर्गत डिमि के अथाबाड़ी में बीती मध्य रात्रि को दो दुकानों में आग लग गई। इसके बाद आग ने पास की एक अन्य मोबाइल दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। इसके परिणामस्वरूप, दोनों दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान जल गया। डिमि और शिवासागर से अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग शांत सर्किट की वजह से लगने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

बाक्स ने ऐतिहासिक झुमुर नृत्य प्रदर्शन के लिए भेजे 64 प्रतियोगी

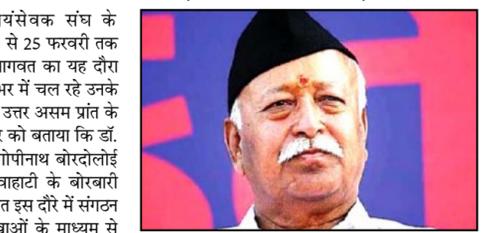
विकसित भारत समाचार बाक्स। जिला आयुक्त गौतम दास ने 20 फरवरी को बाक्स जिले से 64 प्रतिभागियों को लेकर गुवाहाटी के लिए दो बसों को हरी झंडी दिखाई। झूमुरी टी एस्टेट (बाक्स) और फातिमाबाद टी एस्टेट (मानस लेक) के नर्तक भव्य झुमुर नृत्य प्रदर्शन में भाग लेंगे, जो 24 फरवरी को इतिहास रचने वाला है। असम एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, झुमुर बिनादिनी के लिए तैयार हो रहा है, जिसमें 27 जिलों के 9,000 से अधिक कलाकार राज्य की समृद्ध चाय बागान संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। असम चाय के 200 साल पूरे होने का जश्न मनाने वाला यह भव्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में गुवाहाटी के सरसजाई स्टेडियम में होगा। इस अवसर पर बोलते हुए, डीसी गौतम



दास ने प्रतिभागियों पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि यह बाक्स जिले के लिए गर्व का क्षण है। हमारे प्रतिभाशाली नर्तक असम की जीवंत परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले ऐतिहासिक प्रदर्शन का हिस्सा होंगे। मैं उन्हें इस भव्य मंच पर हमारे जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए

संघ प्रमुख मोहन भागवत शुक्रवार से असम के पांच दिवसीय दौरे पर

गुवाहाटी (हिस)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक डॉ. मोहन भागवत 21 से 25 फरवरी तक असम के दौरे पर आ रहे हैं। डॉ. भागवत का यह दौरा संघ के शताब्दी वर्ष के महानजर देशभर में चल रहे उनके प्रवास का ही एक हिस्सा है। संघ के उत्तर असम प्रांत के प्रचार प्रमुख किशोर शिवम ने गुरुवार को बताया कि डॉ. मोहन भागवत शुक्रवार दोपहर को गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सीधे गुवाहाटी के जोरबारी स्थित सुदर्शननालय पहुंचेंगे। डॉ. भागवत इस दौरे में संगठन कार्य विस्तार, कार्य की दृढ़ता, शाखाओं के माध्यम से समाज में परिवर्तन जैसे विषयों पर स्वयंसेवकों के साथ विचार-विमर्श करेंगे। शिवम के मुताबिक समाज परिवर्तन के महानजर संघ के पांच मुख्य पहल-सामाजिक समरसता, नागरिक कर्तव्य, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी और कुटुंब प्रबोधन को स्वयंसेवकों के माध्यम से समाज के सभी स्तरों तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर भी वे अपना विचार प्रस्तुत करेंगे। वे गुवाहाटी महानगर की दो शाखाओं में उपस्थित रहकर वहां की टोली बैठकों में भी उपस्थित



रहेंगे। 22 फरवरी की शाम को वे आईआईटी गुवाहाटी में राष्ट्र सेविका समिति की बैठक में भाग लेंगे। 23 फरवरी की सुबह साउकुची स्थित साउथ व्वाइंट हाई स्कूल प्रांगण में डॉ. भागवत एक बौद्धिक कार्यक्रम में उपस्थित रहकर गुवाहाटी महानगर के स्वयंसेवकों के समक्ष बौद्धिक व्याख्यान देंगे। इस दौरान वे कई और सांठनिक बैठकों में भी भाग लेंगे। 26 फरवरी की सुबह डॉ. भागवत अरुणाचल प्रदेश के लिए प्रस्थान करेंगे।

सरकार ने कोई भी सर्किल ऑफिस बंद नहीं किया : मुख्यमंत्री

गुवाहाटी (हिस)। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने स्पष्ट किया है कि असम सरकार ने किसी भी सर्किल ऑफिस को बंद करने का निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्रों के हुए पुनर्गठन के सिलसिले में सरकार ने यह आदेश अवश्य दिया था कि पदाधिकारी स्थानीय लोगों तथा विधायकों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करें कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में सर्किल ऑफिस हो। मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा गुरुवार को असम विधानसभा के चालू बजट सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए उपरोक्त बातें कही। ज्ञात हो कि राज्यपाल के अभिभाषण पर विधायक रूपक शर्मा द्वारा लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक अब्दुर रशीद मंडल समेत अन्य कई विधायकों ने सर्किल ऑफिस को बंद नहीं करने का आग्रह किया था। विधायकों का कहना था कि सर्किल ऑफिस बंद किए जाने की वजह से स्थानीय भूमि संबंधी समस्याओं के निपटारा के लिए लोगों को कई किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने अपने जवाब में यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी सर्किल कार्यालय को बंद करने संबंधी कोई भी निर्णय सरकार द्वारा नहीं लिया गया है।

सिलचर में मिशन शक्ति के तहत हितधारकों की संयुक्त बैठक

सिलचर। महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा, लैंगिक भेदभाव को रोकने एवं जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सिलचर में एक महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बुधवार को जिला आयुक्त कार्यालय के नए सम्मेलन कक्ष में आयोजित बैठक मिशन शक्ति एजेंडे के तहत आयोजित की गई थी। संकल्प-जिला महिला सशक्तिकरण केंद्र (कछार) और महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस बैठक को यूनिसेफ की सहयोगी संस्था इंडिपेंडेंट थॉट और कछार जिला प्रशासन की सक्रिय भागीदारी से और अधिक महत्वपूर्ण बनाया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के महत्व, उनकी सुरक्षा और शिक्षा को और मजबूत करना था, विशेष रूप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) एजेंडे की 10वीं वर्षगांठ मनाने के उद्देश्य से। बैठक का मुख्य उद्देश्य संकल्प, सामर्थ्य और बीबीबीपी परिशोजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, बाल विवाह को रोकथाम करना, लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करना और सभी बालिकाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना था। बैठक की शुरुआत में महिला एवं बाल कल्याण विभाग की प्रभारी अतिरिक्त जिला



आयुक्त किमचिन लंघम ने सरकारी और निजी संगठनों के बीच समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण और बाल संरक्षण के लिए मिलकर काम करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन सहित समाज के हर स्तर की इसमें सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। जिला समाज कल्याण विभाग की सहायक आयुक्त अंजलि कुमारी और संकल्प की डीएमसीएच बनानी भट्टाचार्य ने मिशन शक्ति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से चर्चा की। वे परिशोजनाओं की वर्तमान प्रगति, मौजूदा समस्याओं और भविष्य की योजनाओं का वर्णन करते हैं। इस बीच,

181 (महिला हेल्पलाइन) और 1098 (बाल हेल्पलाइन) के कामकाज को बढ़ावा देने और सुदृढ़ करने पर जोर दिया जा रहा है। ताकि किसी भी आपदा पीड़ित को समय मिलकर काम करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन सहित समाज के हर स्तर की इसमें सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। जिला समाज कल्याण विभाग की सहायक आयुक्त अंजलि कुमारी और संकल्प की डीएमसीएच बनानी भट्टाचार्य ने मिशन शक्ति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से चर्चा की। वे परिशोजनाओं की वर्तमान प्रगति, मौजूदा समस्याओं और भविष्य की योजनाओं का वर्णन करते हैं। इस बीच,

विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) की सचिव सलमा सुल्ताना ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम (पीओएसएच) के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बाल दुर्व्यवहार, शोषण और जबरन विवाह जैसे अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आह्वान किया। इस संयुक्त बैठक में जिला प्रशासन, जिले के महिला एवं बाल कल्याण विभाग तथा यूनिसेफ की सहयोगी संस्था इंडिपेंडेंट थॉट के सशक्त संयुक्त प्रयास पर प्रकाश डाला गया। बैठक में प्रतिभागियों ने बालिकाओं के लिए सुरक्षित, संरक्षित और गैर-भेदभावपूर्ण समाज बनाने के लिए अधिक प्रभावी नीतियों और प्रणालियों की आवश्यकता पर चर्चा की। इस संयुक्त प्रयास से एक नया क्षितिज खुलेगा, जिससे प्रत्येक बालिका का सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा, उनके सपनों को पूरा करने में कोई बाधा नहीं आएगी तथा वे एक उज्वल भविष्य का निर्माण करने में सक्षम होंगी। समाज के सभी स्तरों के समर्थन से भेदभाव को समाप्त करना तथा सशक्त एवं सुरक्षित बालिकाओं का विकास संभव है। यह जानकारी सिलचर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञापन में दी गई।

संपादकीय

अश्लीलता-अभद्रता की हद्द

हाल के दिनों में सोशल मीडिया से जुड़े प्लेटफॉर्मों के कार्यक्रमों में स्वेच्छाचारिता और वर्जनाएं तोड़ने के अनगिनत मामले प्रकाश में आए हैं। जो भारतीय सामाजिक व पारिवारिक मूल्यों का अतिक्रमण करते हुए अराजक व्यवहार कर रहे हैं। पिछले दिनों संसद से लेकर सड़क तक यूट्यूब पर प्रसारित एक फूहड़ व अभद्र कार्यक्रम के खिलाफ कार्रवाई की मांग गुंजती रही, जिसमें अभद्रता से सामाजिक मर्यादा की सीमाएं लांघने की कुत्सित कोशिश हुई। पिछले दिनों कॉमेडियन समय रेना के यूट्यूब शो 'इंडियाज गॉट टैलेंट' में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर व यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने एक अश्लील, अभद्र व अमर्यादित टिप्पणी की। इस बदमिजाज यूट्यूबर ने शो के एक प्रतिभागी के माता-पिता के अंतरंग पलों के बारे में घोर निंदाजनक प्रश्न किए। जैसा अपेक्षित था,

राष्ट्रीय परिवार व सांस्कृतिक मूल्यों पर हमला करने वाली टिप्पणी पर देश में भारी विवाद हुआ। देश के विभिन्न भागों में इस मामले में शिकायतें दर्ज की गईं, और राष्ट्रीय महिला आयोग ने ऐसे कार्यक्रमों के नियमन की मांग करते हुए कार्रवाई की सिफारिश की। साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूट्यूब से इस विवादित कार्यक्रम को हटाने के निर्देश दिए। देश के राजनीतिक क्षेत्रों में भी इस विवाद को लेकर तीखी टिप्पणियां सामने आईं। इस विवाद ने देश में इस बहस को एक बार फिर तेज किया कि सामाजिक मूल्यों को लेकर अभिव्यक्तियों की आजादी पर हमला करने वाली टिप्पणी पर देश में भारी विवाद हुआ। देश के विभिन्न भागों में इस मामले में शिकायतें दर्ज की गईं, और राष्ट्रीय महिला आयोग ने ऐसे कार्यक्रमों के नियमन की मांग करते हुए कार्रवाई की सिफारिश की। साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूट्यूब से इस विवादित कार्यक्रम को हटाने के निर्देश दिए। देश के राजनीतिक क्षेत्रों में भी इस विवाद को लेकर तीखी टिप्पणियां सामने आईं। इस विवाद ने देश में इस बहस को एक बार फिर तेज किया कि सामाजिक मूल्यों को लेकर अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा के निर्धारण और डिजिटल कंटेंट निर्माताओं की जवाबदेही कैसे तय की जाए। साथ ही रचनात्मक अभिव्यक्ति तथा सार्वजनिक शिष्टाचार में सामंजस्य कैसे बनाया जाए। दरअसल, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर लाइक और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिये तमाम फूहड़ व तलछीभरे कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाता है, ताकि इससे यूट्यूबर्स की आय बढ़ सके। बदलते वक्त की विडंबना यह है कि धीरे-गंभीर व उपयोगी कार्यक्रमों को दर्शकों का वह प्रतिसाद नहीं मिलता, जो ऊल-जलूल कार्यक्रमों को मिलता है। इन कार्यक्रमों के ज्यादा देखे जाने से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का वित्तीय नुक़ान भी बढ़ता है। इसी होड़ में अमर्यादित और विवादास्पद कार्यक्रमों की शृंखला का जन्म होता है। ऐसे में सवाल उठता जा रहा है कि क्या सोशल मीडिया नियमन को लेकर बने कानून इस अराजकता पर अंकुश लगाने में सक्षम हैं? क्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिये प्रसारित सामग्री पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को सख्त बनाने की जरूरत है? क्या अश्लील अभिव्यक्ति को दंडनीय बनाने के लिये सख्त कानूनों की जरूरत है? सवाल यह भी है कि हंसें मजाक के कार्यक्रमों के लिये सामाजिक मर्यादाओं की सीमा कैसे तय की जाए? जाहिए है अब वक्त आ गया है कि मनोरंजक हास्य कार्यक्रमों और आधुनिक कंटेंट के बीच सीमा का निर्धारण किया जाए। निरसंदेश, किसी लोकातीक देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपरिहार्य शर्त है, लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि हम तमाम सामाजिक व पारिवारिक मर्यादाओं को ताक पर रख दें। किसी भी सूरत में सोशल मीडिया को एंटी सोशल अभिव्यक्ति की आजादी नहीं दी जा सकती। निरसंदेश, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को कंटेंट के बाबत जवाबदेह बनाने की जरूरत है। इसके संचालकों को चाहिए कि रचनात्मक स्वतंत्रता के नाम पर सार्वजनिक शिष्टाचार का अतिक्रमण न करें।

सामाजिक मूल्यों को लेकर अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा के निर्धारण और डिजिटल कंटेंट निर्माताओं की जवाबदेही कैसे तय की जाए। साथ ही रचनात्मक अभिव्यक्ति तथा सार्वजनिक शिष्टाचार में सामंजस्य कैसे बनाया जाए। दरअसल, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर लाइक और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिये तमाम फूहड़ व तलछीभरे कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाता है, ताकि इससे यूट्यूबर्स की आय बढ़ सके। बदलते वक्त की विडंबना यह है कि धीरे-गंभीर व उपयोगी कार्यक्रमों को दर्शकों का वह प्रतिसाद नहीं मिलता, जो ऊल-जलूल कार्यक्रमों को मिलता है।

कुछ अलग

हमारी किस्मत के पकौड़े

उबलते तेल की कड़ाही से उछल कर एक पकौड़ा बाहर निकला। वह चीखा तो हलवाई ने उसे बेददी से घूरा। हलवाई के लिए अब वह दो कौड़ी की भी नहीं था, हालांकि कुछ देर पहले तक उसे अपने हाथों से खिलाया, नचाया और उबलते तेल की कड़ाही में जन्म दिया था। वह अपने सहयोगियों-सहपाठियों की संगत में किसी से कम नहीं था। उसका वजन और शकल-सूरत किसी भी प्लेट में रखने लायक थी, लेकिन उसका उछलना उसे बर्बाद कर गया। वह पकौड़ा खा, इसलिए किसी का रोजगार, किसी का व्यापार और किसी का स्वाद था। पकौड़ों को देख-देख हम हिंदोस्तानी भी रोजगार हासिल करना सीख गए। अगर सारी दुनिया पकौड़े खाना सीख ले, तो हम इस आर्थिकी के प्रमुख किस्मदार होंगे। अब बर्गर-पिज्जा के बीच सबसे सुंदर तो हमारा पकौड़ा ही है, लेकिन इसका रोजगार छीना जा रहा है। हम इंडियन भी कमाल हैं पकौड़े घर छोड़कर बर्गर, पिज्जा और मोमो बेच रहे हैं। कड़ाही से गिरे हुए पकौड़े एक फकीर ने उठा लिए। फकीर लाभ में था क्योंकि उसे मुफ्त में पेट भरने का मौका मिल गया। यह विशेषता भी भारतीय पकवान की है। ये गिरते-गिरते भी कूड़ेदान तक पेट में चलते हैं। दूसरी ओर बर्गर-पिज्जा को किसी ने गिरते नहीं देखा। इधर राष्ट्रीय पकवान के मुकाबले में गली-गली तक पहुंच कर पका मोमो बन रहा है। हम चीन का मुकाबला कम से कम मोमो से तो कर ही रहे हैं। जितने मोमो चीन पका ही नहीं सकता, हम पका रहे हैं। इन्हें खाने का रिकार्ड भी हम बना रहे हैं। पकौड़ों से डाक्टर लोग नफरत करते हैं, जबकि मोमो खाने वालों के इंतजार में चिकित्सा का धंधा चमक रहा है। वैसे हमारी विदेश नीति अब बर्गर-पिज्जा जैसी

हो गई है। वही आसान सी रीसिपी और परत पर चढ़ी परत। हमें देखते ही टंप को भी एहसास होने लगा है कि उसका बर्गर तब तक भारत में महफूज है जब तक बदले में हमें वह कुछ भी बेचना रहेगा। निरसंदेश, किसी लोकातीक देश में बर्गर खिलाकर विदेश नीति बना रहा है, वही अपने देश में भारतीयों से बर्गर छीन रहा है। हद है कि हम अपनी भूख को बर्गर दिखाकर शांत करने लग पड़े हैं, लेकिन अमरीका की भूख हमें भूखा रखना चाहती है। वह चाहती है कि हम एक अदद पकौड़ा खाने योग्य भी न रहें। विदेश मंत्री जिस दिन अमरीका को पकौड़ा वार्ता के लिए तैयार कर लेंगे, सब कुछ बदल जाएगा। पहले ही पकौड़ा वार्ता की होती, तो अमरीका से भारतीय निवासित न होते। टंप को समर सय रहते पकौड़े के गुण बताने होंगे। बताना होगा कि अगर हम पकौड़ा जिद्द पर आ गए, तो अमरीका का माल अमरीका में ही रह जाएगा। पकौड़ा खाकर हम पैदल भी चल सकते हैं, तो उनकी हालें डेविडसन बाइक का क्या होगा। हम हालें बाइक से आयात कर हटा कर भी महंगी जीएसटी के पकौड़े खा लेंगे। अगर हमसे पकौड़े न खाए होते तो तुम्हारी बेडियां-हथकड़ियां हमें तोड़ देतीं। हम टूटें कहां, हम तो जिंदा हैं। अमानवीय निवासित होकर भी खाते हैं। दूसरी ओर बर्गर-पिज्जा को ललक रही, तो पुनः इसी तरह तुम्हारी हद में घुस जायेंगे। हम हद से बाहर और बेहद होकर भी जी लेते हैं। हमने मुफ्त का राशन खाना था, तुम्हारे पिज्जा-बर्गर की क्या हैसियत जो हमें भूखा मारे। टंप को भारतीयों की क्षमता से खतरा पैदा हो गया है। देश में निखड़ वहां अमरीका में कैसे अब्जल साबित हो गए। टंप ने सोचा, 'ये लोग वाकई घुस सकते हैं और घुस जाते हैं। हद तो यह कि बातों-बातों में दोस्ती के भी गले पड़ जाते हैं।'

अभियुक्त द्वारा अभियोक्ता को यौन गतिविधि में शामिल होने के लिए लुभाने के लिए लुभाने के इरादे के बिना किया गया वादा बलात्कार के रूप में मान्य नहीं होगा

विवाह के झूठे वादों से दुष्कर्म के बढ़ते मामले

प्रियंका सौरभ

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अनुल गौतम मामले में 2025 में दिए गए फैसले से यह सवाल उठता है कि न्यायिक व्याख्याएँ महिलाओं की स्वायत्तता और कानूनी सुरक्षा को कैसे प्रभावित करती हैं। बलात्कार और सेक्स के लिए सहमति देना स्पष्ट रूप से अलग-अलग हैं। इन स्थितियों में, न्यायालय को सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए कि क्या शिकायतकर्ता की पीड़िता से शादी करने की वास्तविक इच्छा थी या उसके कोई छिपे हुए उद्देश्य थे और उसने केवल अपनी वासना को शांत करने के लिए इस आशय का झूठा वादा किया था, क्योंकि बाद वाले को धोखा या छल माना जाता है। इसके अतिरिक्त, झूठा वादा न सिर्फ शादी और उसे तोड़ देने में अंतर है। अभियुक्त द्वारा अभियोक्ता को यौन गतिविधि में शामिल होने के लिए लुभाने के इरादे के बिना किया गया वादा बलात्कार के रूप में मान्य नहीं होगा। अभियोक्ता अभियुक्त द्वारा बनाए गए झूठे प्रभाव के बजाय उसके प्रति अपने और अनुजून के आधार पर अभियुक्त के साथ यौन सम्बंधों के लिए सहमति दे सकती है। वैकल्पिक रूप से, अप्रत्याशित या अनिर्दिष्ट परिस्थितियों के कारण ऐसा करने का इरादा होने के बावजूद अभियुक्त उससे शादी करने में असमर्थ हो सकता है। इन स्थितियों को अलग तरीके से संभालने की आवश्यकता है। बलात्कार का मामला तभी स्पष्ट होता है जब शिकायतकर्ता का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा या गुप्त उद्देश्य हो। अनुल गौतम बनाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है। यह फैसला अर्पाण भट बनाम के विपरीत है। 2021 के मध्य प्रदेश राज्य के फैसले में आरोपी और पीड़ित को द्वितीयक आवास से बचने के लिए जमानत पर रहते हुए संवाद करने से मना किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी के लिए, जमानत की आवश्यकताओं को आरोपी और उत्तरजीवी के बीच संचार के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। यह विचार कि विवाह बलात्कार के लिए एक उपाय है न कि अपराध के लिए सजा, ऐसी जमानत आवश्यकताओं द्वारा पुष्ट होता है, जो सामाजिक समझौते को कानून के शासन से आगे रखता है। रामा शंकर बनाम उत्तर प्रदेश

राष्ट्रीय अपराधरिकॉर्डब्यूरो (एनसीआरबी) की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि हर साल झूठी शादी की शपथ की आड़ में कई हज़ार बलात्कार के मामले दर्ज किए जाते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अनुल गौतम मामले में 2025 में दिए गए फैसले से यह सवाल उठता है कि न्यायिक व्याख्याएँ महिलाओं की स्वायत्तता और कानूनी सुरक्षा को कैसे प्रभावित करती हैं। बलात्कार और सेक्स के लिए सहमति देना स्पष्ट रूप से अलग-अलग हैं। इन स्थितियों में, न्यायालय को सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए कि क्या शिकायतकर्ता की पीड़िता से शादी करने की वास्तविक इच्छा थी या उसके कोई छिपे हुए उद्देश्य थे और उसने केवल अपनी वासना को शांत करने के लिए इस आशय का झूठा वादा किया था, क्योंकि बाद वाले को धोखा या छल माना जाता है। इसके अतिरिक्त, झूठा वादा न सिर्फ शादी और उसे तोड़ देने में अंतर है। अभियुक्त द्वारा अभियोक्ता को यौन गतिविधि में शामिल होने के लिए लुभाने के इरादे के बिना किया गया वादा बलात्कार के रूप में मान्य नहीं होगा। अभियोक्ता अभियुक्त द्वारा बनाए गए झूठे प्रभाव के बजाय उसके प्रति अपने और अनुजून के आधार पर अभियुक्त के साथ यौन सम्बंधों के लिए सहमति दे सकती है। वैकल्पिक रूप से, अप्रत्याशित या अनिर्दिष्ट परिस्थितियों के कारण ऐसा करने का इरादा होने के बावजूद अभियुक्त उससे शादी करने में असमर्थ हो सकता है। इन स्थितियों को अलग तरीके से संभालने की आवश्यकता है। बलात्कार का मामला तभी स्पष्ट होता है जब शिकायतकर्ता का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा या गुप्त उद्देश्य हो। अनुल गौतम बनाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है। यह फैसला अर्पाण भट बनाम के विपरीत है। 2021 के मध्य प्रदेश राज्य के फैसले में आरोपी और पीड़ित को द्वितीयक आवास से बचने के लिए जमानत पर रहते हुए संवाद करने से मना किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी के लिए, जमानत की आवश्यकताओं को आरोपी और उत्तरजीवी के बीच संचार के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। यह विचार कि विवाह बलात्कार के लिए एक उपाय है न कि अपराध के लिए सजा, ऐसी जमानत आवश्यकताओं द्वारा पुष्ट होता है, जो सामाजिक समझौते को कानून के शासन से आगे रखता है। रामा शंकर बनाम उत्तर प्रदेश



राज्य (2022) में जमानत देते समय इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिसने प्रतिवादी के खिलाफ अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर कर दिया। उत्तरजीवी को जमानत प्राप्त करने के लिए आरोपी द्वारा विवाह के लिए मजबूर किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कानूनी बन्धन के भीतर निरंतर दुर्व्यवहार हो सकता है। अभिषेक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024) ने न्याय की गारंटी देने के बजाय, अभियुक्त को विवाह के उद्वेग के बदले में जमानत देकर एक दबावपूर्ण गतिशीलता बनाई। जो उत्तरजीवी को उचित पुनर्वास सहायता प्राप्त करने के बजाय अभियुक्त पर निर्भर रहने के लिए मजबूर करता है। किशोरों के निजता के अधिकार (2024) में न्यायालय द्वारा उत्तरजीवियों और बच्चों को आवास, शिक्षा और परामर्श प्रदान करने के राज्य के दायित्व पर प्रकाश डाला गया था। जमानत का उद्देश्य सामाजिक कर्तव्यों को लागू करना नहीं है, बल्कि मामला लंबित रहने तक अस्थायी स्वतंत्रता की गारंटी देना है। महिलाओं की स्वायत्तता और इस्मान्तर विचारधारा की निरंतरता इन न्यायिक निर्णयों से प्रभावित होती है, जो लैंगिक रूढ़ियों को भी मजबूत करती हैं। ऐसे निर्णय बलात्कार को अपराध से कम और पवित्रता के नुक़सान को अधिक बनाते हैं, जो पितृसत्तात्मक धारणा को मजबूत करते हैं कि एक महिला की गरिमा विवाह से जुड़ी होती है। न्यायालयों ने पिछले कई निर्णयों में एक पीड़ित के पुनर्वास को विवाह के बराबर माना है, बलात्कार को शारीरिक स्वायत्तता के उल्लंघन के रूप में स्वीकार करने में विफल रहे। न्यायालय महिलाओं की स्वायत्तता को कमजोर करते हुए अपराधियों के साथ विवाह करने के लिए पीड़ितों पर दबाव डालकर कानूनी संरक्षण के तहत दुर्व्यवहार और नियंत्रण को बढ़ावा देते हैं। विवाह को एक उपाय मानने वाली

अदालतें पीड़ित की सहमति की कमी को नजर अंदाज करती हैं, जिसका अर्थ है कि जबर्दस्ती को कानूनी रूप से उचित ठहराया जा सकता है। महिलाओं को लगातार आघात और सुरक्षा जोखिमों विवाह में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करते हुए, जो महिलाओं की स्वायत्तता और गरिमा की रक्षा करता है, ऐसे निर्णय महिलाओं को उनकी इच्छा के विरुद्ध सम्बंधों में मजबूर करके उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, जबनन विवाह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करते हैं, जिससे पीड़ितों को न्याय के बजाय अधिक शोषण का सामना करना पड़ता है। ये निर्णय इस धारणा को बनाए रखते हैं कि विवाह यौन हिंसा को हल कर सकता है, इन घटनाओं को गंभीर अपराधों के बजाय नागरिक विवादों में बदल देता है। रूढ़िवादी ग्रामीण क्षेत्रों में पीड़ितों पर अक्सर अदालतों द्वारा आरोपी लड़के को विवाह करने का दबाव होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामाजिक दबाव से न्याय से समझौता न हो, अदालतों को स्थापित नियमों का पालन करना चाहिए जो विवाह को जमानत की शर्त बनाने से रोकेते हैं। अर्पाण भट केस (2021) में, सर्वोच्च न्यायालय ने फ़ैसला किया कि जमानत की ऐसी आवश्यकताएँ जो पीड़ितों को रिश्तों में मजबूर करती हैं या लैंगिक रूढ़िवादिता को बनाए रखती हैं, उनसे बचना चाहिए। राज्य को पीड़ितों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करने के लिए मौद्रिक सहायता, परामर्श, कानूनी सहायता और कौशल-निर्माण कार्यक्रम प्रदान करके कल्याण कार्यक्रमों में सुधार करना चाहिए वन स्टॉप सेंटर योजना द्वारा एकीकृत सहायता सेवाएँ प्रदान की जाती हैं; हालाँकि, अधिकतम प्रभाव के लिए, इसमें सुधार और विस्तार की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायिक विवेक से पीड़ितों के अधिकारों को खतरा न हो, विधायी संशोधनों को विशेष रूप से विवाह की शर्त पर जमानत देने की प्रथा को रोकना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कानूनी व्याख्याएँ पितृसत्तात्मक पूर्वाग्रहों के बजाय संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखें, न्यायाधीशों को लिंग-संवेदनशील प्रशिक्षण प्रदान करें। पीड़ितों के अधिकारों और लैंगिक न्याय को न्यायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए, जैसे कि राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा संचालित कार्यक्रम।

दृष्टि कोण

डिजिटल कंटेंट और अभिव्यक्ति की आजादी

सोशल मीडिया ने हमारे एक-दूसरे से जुड़ने और बातचीत करने के तरीके में क्रांति ला दी है। इसने एक नई घटना को भी जन्म दिया है: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर वे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में फॉलोअर जुटाए हैं और अपने फॉलोअर्स की राय और व्यवहार को प्रभावित करने में सक्षम हैं। जबकि इन्फ्लुएंसर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, युवा दिमाग पर उनके प्रभाव के बारे में चिंता बढ़ रही है। इन्फ्लुएंसर्स को अक्सर रोल मॉडल और ट्रेंडसेटर के रूप में देखा जाता है, खासकर युवा लोगों के बीच। उन्हें अक्सर फेल्सता, लोकप्रियता और सुंदरता के अवतार के रूप में देखा जाता है। इससे 'आकांक्षी' सामग्री के चलन में वृद्धि हुई है, जहां इन्फ्लुएंसर्स अपनी शानदार जीवनीयों का प्रदर्शन करते हैं और ऐसे उत्पादों का प्रचार करते हैं जो उनके अनुयायियों को उनके जैसा बनाने का वादा करते हैं। हालांकि, प्रभावशाली लोग जिस सामग्री को बढ़ावा देते हैं, वह हमेशा सकारात्मक या स्वस्थ नहीं होती। कई प्रभावशाली लोग अवास्तविक शारीरिक मानकों के

बढ़ावा देते हैं, जो उनके अनुयायियों के बीच शरीर के असंतोष और खाने के विकारों में योगदान कर सकते हैं। वे भौतिकवाद और उपभोक्तावाद को भी बढ़ावा देते हैं, अपने अनुयायियों को ऐसे उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं है या वे खरीद नहीं सकते हैं। अस्वस्थ व्यवहार को बढ़ावा देने के अलावा, प्रभावशाली लोग युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नशे की लत के लिए डिजाइन किया गया है, और कई युवा लोग अपने फीड को स्क्रॉल करने में घंटों बिताते हैं, खुद की तुलना दूसरों से करते हैं और अपर्याप्त महसूस करते हैं। प्रभावशाली लोगों की ब्यूट्री और संपादित सामग्री वास्तविकता का एक विकृत दृश्य बना सकती है, जिससे युवा लोगों को लगता है कि वे अपने साथियों या खुद के आदर्श संस्करण के बराबर नहीं हैं जो वे ऑनलाइन देखते हैं। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि प्रभावशाली लोग स्वाभाविक रूप से बुरे या हानिकारक नहीं होते हैं। कई लोग अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग सकारात्मक संदेशों को बढ़ावा देने के लिए करते हैं, जैसे

कि शरीर की सकारात्मकता, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और सामाजिक न्याय। हालांकि, हम जो सामग्री देखते हैं, उसके बारे में आलोचनात्मक होना और उसके पीछे के उद्देश्यों पर सवाल उठाना महत्वपूर्ण है। हमें इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए कि प्रभावशाली लोगों को अक्सर उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भुगतान किया जाता है, और हो सकता है कि उनकी सामग्री पूरी तरह से वास्तविक न हो। माता-पिता और शिक्षकों को भी युवाओं को सोशल मीडिया की दुनिया में आगे बढ़ने में मदद करने में भूमिका निभानी चाहिए। उन्हें मीडिया साक्षरता कौशल सिखाकर, हम युवाओं को उनके द्वारा देखी जाने वाली सामग्री का गंभीरता से मूल्यांकन करने और इसे अपने निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं कि वे किससे जुड़ना चाहते हैं। निष्कर्ष में, सोशल मीडिया के प्रभावशाली लोग युवा दिमाग पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से शक्तिशाली प्रभाव डाल सकते हैं, जबकि हमें संभावित जोखिमों के बारे में सावधान रहना चाहिए। हमें यह भी पहचानना चाहिए कि प्रभावशाली लोग प्रेरणा और सकारात्मक रोल मॉडल का स्रोत हो सकते हैं। मीडिया

साक्षरता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देकर, हम युवाओं को स्वस्थ और उत्पाक तरीके से सोशल मीडिया की दुनिया में नेविगेट करने में मदद कर सकते हैं। भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने व अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या वाक स्वतंत्रता किसी व्यक्ति या समुदाय द्वारा अपने मत और विचार को बिना प्रतिशोष, अभिवेचन या डंड के डर के प्रकट कर पाने की स्थिति होती है। इस स्वतंत्रता को सरकारें, जनसंचार कम्पनियां और अन्य संस्थाएँ बाधित कर सकती हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 19 में प्रयुक्त 'अभिव्यक्ति' शब्द इसके क्षेत्र को बहुत विस्तृत कर देता है। अंतर्राष्ट्रीय के व्यक्त करने के जितने भी माध्यम हैं, वे अभिव्यक्ति, पदावली के अंगत आ जाते हैं। स्वतंत्र प्रसारण ही इस स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य है। यह भाषण द्वारा या समाचारपत्रों द्वारा किया जा सकता है। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद आधी से अधिक युवतियों ने ऑनलाइन उन्नीयन या दुर्व्यवहार का सामना किया है। एक नए सर्वेक्षण में इस बात का पता चला है।

देश दुनिया से

भ्रष्टाचार मिटाने को जिम्मेदारी तय हो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए एजेंसियों को खुली छूट दे दी है और इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार एक दीमक है जिसने देश को खोखला कर दिया है और वह देश को इस बुराई से मुक्त करने के लिए पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस दुर्निश्चय के बावजूद भारत में भ्रष्टाचार कैसर की तरह फैलता जा रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार हो या राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें, सभी भ्रष्टाचार के विरुद्ध बड़े दावे-वादे करती रह गईं, किंतु यह समस्या सुरसा के मुंह की तरह विकराल होती जा रही है। करफण परसेप्शन इंडेक्स-2024 की भ्रष्टाचार की सूचकांक में भारत 96 वें पायदान पर पहुंच गया है। साल 2023 में भारत की रैंक 93 थी। भारत इस सूची में पड़ोसी देशों की ज्यादा बुरी हालत पर कुछ राहत महसूस कर सकता है। भ्रष्टाचार की इस सूची में भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान 135 नंबर पर और श्रीलंका 121 पर हैं, जबकि बंगलादेश की रैंकिंग और भी नीचे 149 पर चली गई है। इस लिस्ट में चीन 76वें स्थान पर है। डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट राष्ट्र होने की सूची में सबसे ऊपर है, उसके बाद फिनलैंड और सिंगापुर हैं। 1995 से 2024 तक भारत में भ्रष्टाचार की औसत दर 78.03 रही, जो 2024 में 96.00 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। प्रत्येक देश का स्कोर 13 विभिन्न भ्रष्टाचार संवेद्यताओं और कानूनों से प्राप्त कम से कम 3 डेटा स्रोतों से लिया जाता है। ये सोर्स विश्व बैंक और विश्व आर्थिक मंच सहित विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा एकत्र किए जाते हैं। सीपीआई की गणना करने की प्रक्रिया की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जर्मि की जारी की जाने वाली सूची यथार्थभव बनत और सुसंगत है या नहीं? भारत में विदेशी निवेश अपेक्षाकृत नहीं आने का एक प्रमुख कारण भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के कारण भारत की अंतरराष्ट्रीय साख कमजोर है। विदेशी कंपनियां यहां निवेश करने से कतराती हैं। देश के उद्योगपति और लघु व मध्यम व्यवसायी इसकी भार से बच नहीं सके हैं। भारत एक तरफ वैश्विक ताकत बनने की दिशा में अग्रसर है, वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की जंजीर इसके बढ़ते कदम को रोक रही है। ऐसा देश का शायद ही कोई चुनाव होगा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार का जिक्र नहीं किया हो। मोदी ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं को चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार पर प्रहार करने में कसर बाकी नहीं रखी। संसद में दिए गए भाषण में उन्होंने कहा था कि मेरे लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चुनावी जीत या हार के पैमाने पर नहीं है। मैं चुनाव जीतने या हारने के लिए भ्रष्टाचार से नहीं लड़ रहा हूँ। यह मेरा मिशन है, मेरा विश्वास है। मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार एक ऐसा दीमक है जिसने देश को खोखला कर दिया है। मैं इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने और आम लोगों के मन में भ्रष्टाचार के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए पूरे दिल से काम कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री के देश से पूरी तरह भ्रष्टाचार के

खात्मे के प्रति प्रतिज्ञा लेने के बावजूद यदि यह संक्रामक रोग की तरह बढ़ता ही जा रहा है, तो इसके लिए ज्यादातर राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं। क्षेत्रीय दलों की हालत यह है कि उनका एकमात्र कसकद किसी भी हालत में सत्ता में बने रहना है। इसके लिए बेशक भ्रष्टाचार से किसी भी हद तक समझौता क्यों न करना पड़े। यही वजह रही है कि इंडिया गठबंधन लगातार चुनावों में शिकस्त खाता रहा है। आश्चर्य यह है कि लोकसभा चुनावों और राज्यों के विधानसभा चुनावों में करारी हार के बावजूद विपक्षी दलों ने भ्रष्टाचार को कभी भी प्रमुख चुनावी मुद्दा नहीं बनाया। भ्रष्टाचार को लेकर हालात ये हैं कि जैसे ही कोई भी विपक्षी दल भ्रष्टाचार का जिक्र करता है, तत्काल सत्तारूढ़ दल न सिर्फ उसके बचाव में उतर आता है, बल्कि विपक्षी दल के कानामे गिनाने लगता है। यही वजह है कि क्षेत्रीय दल अपने राज्यों में मनमानी करने पर आमदा हैं। यदि केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय कोई कार्रवाई करता है, तो राज्य के सत्तारूढ़ दल इसे बदले की कार्रवाई करने देने लगते हैं। इसका उदाहरण पश्चिमी बंगाल की ममता बनर्जी सरकार, तमिलनाडु की स्टालिन सरकार और कर्नाटक की सिद्धारमैया की सरकार है। इतना ही नहीं, राजनीतिक दलों का भरसक प्रयास होता है कि अदालतों में चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों की भी प्रभावित किया जाए। गौरतलब है कि सीनियर वकील हरीश सल्वे सहित देश के 600 से ज्यादा वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर न्यायपालिका पर सवाल उठाने को लेकर चिंता जाहिर की थी। सीजेआई को लिखी चिट्ठी में वकीलों ने कहा था कि ये समूह न्यायिक फैसलों को प्रभावित करने के लिए दबाव की रणनीति अपना रहा है और ऐसा खासकर सिविली सीविली हस्तियों और भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े मामलों में हो रहा है। चिट्ठी में कहा गया है कि ये समूह ऐसे बयान देते हैं जो सही नहीं होते हैं और ये राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा करते हैं। अपनी चिट्ठी में वकीलों ने ऐसे कई तरीकों पर प्रकाश डाला है, जिनमें न्यायपालिका के तथ्यांकित 'स्वर्ण युग' के बारे में झूठी कहानियों का प्रचार भी शामिल है। न्यायपालिका तक को प्रभावित करने के प्रयासों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में भ्रष्टाचार किस हद तक व्याप्त है। देश की भ्रष्टाचार में रैंकिंग बेशक बढ़ रही है, इसके बावजूद विगत चुनावों में भाजपा अकेली पाटी रही, जिसने भ्रष्टाचार के खात्मे की बात कही। अन्य दल तो इस मुद्दे पर चर्चा करने तक से कतराते हैं। विपक्षी दलों ने केंद्र के सत्तारूढ़ दल को भ्रष्टाचार में लपेटने की कई बार नाकाम कोशिश की है, चाहे वह मुद्दा युद्धक विमान राफेल की खरीद का हो या अडानी ग्रुप से जुड़ा हुआ हो। विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट तक में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर दूध की थुली है। भाजपा का दामन धामने वाले विपक्षी दलों के नेताओं के ऐसे मामलों को नजरअंदाज किया जाता रहा है। इसके अलावा केंद्र में भाजपा अकेले अपने बलबूतै सत्ता में नहीं है, ऐसे में गठबंधन के सहयोगी दलों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से मुंह फेरे रहती है। यही वजह रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से इन सहयोगी दलों के खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं की गई।

दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने वाले यात्रियों में भगदड़ मच गई, नतीजन 18 मौतें हुईं। उनमें 13 महिलाएँ, 3 बच्चे और 2 पुरुष थे, जो भागदड़ में कुचले गए। घायल की 25 से अधिक बताए गए हैं। अस्पताल के सूत्रों और कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के अनुमान हैं कि मौतों का आंकड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है। बीती शनिवार रात को यह हादसा हुआ, जिसे संस्थान घटना नहीं माना जा सकता। दरअसल यह प्रशासनिक त्रासदी है। अब यह साबित हो गया है कि ऐसी भगदड़ को रोकने में हमारा प्रशासन अक्षम और लापरवाह है। आस्था और अध्यात्म किसी को भी उतेजित न उन्माद और हुड़दंगबाजी को विवश नहीं करते। महाकुंभ में जाने और त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान कर पुण्य कमाने की इच्छा सनातनी और स्वाभाविक है, लेकिन रेलवे स्टेशन की भगदड़ ही अकेली दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं है। बीते दिनों बिहार के पटना और अन्य रेलवे स्टेशनों पर भीड़ के हिंसक चेहरे भी दिखाई दिए। वह भीड़ भी महाकुंभ जाने को आमादा थी। यह संस्कृति ही अराजकता और भगदड़ को जन्म देती है। बिहार में बेलगाम भीड़ ने ट्रेरन के वातानुकूलित डिब्बों के दरवाजे और शीशे ही तोड़ दिए। शीशों पर अलग-अलग चीजों से प्रहार किए गए और वे टूट कर बिखर गए। अंदर बैठे कुछ यात्री चोटिल भी हुए होंगे! भीड़ के विध्वंसक चेहरे सीसीटीवी में कैद हो गए होंगे, यदि वे कैमरे ऑन कार्यरत होंगे! केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन चेहरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। वे आम आदमी और विपन्न घरों के होंगे, तो उनसे आर्थिक जुमाने कैसे वसूल किया जा सकता है? आप जेल में डाल सकते हैं, लेकिन उनके संस्कार ही हमलावर हैं, तो उन्हें कैसे बदला जा सकता है? सार्वजनिक संपत्तियों तो बर्बाद होती रही हैं। ये संपत्तियां कुछ मायनों में महाकुंभ में स्नान करने से भी पवित्र और महत्वपूर्ण हैं। ऐसे तोड़-फोड़ करने और भगदड़ मचाने वाले तत्त्व आध्यात्मिक और आस्थायम नहीं हो सकते। रेल मंत्री अक्षय गिनावरते रहते हैं तो उन्हें कैसे बदला जा सकता है? सार्वजनिक संपत्तियों तो बर्बाद होती रही हैं। ये संपत्तियां कुछ मायनों में महाकुंभ में स्नान करने से भी पवित्र और महत्वपूर्ण हैं। ऐसे तोड़-फोड़ करने और भगदड़ मचाने वाले तत्त्व आध्यात्मिक और आस्थायम नहीं हो सकते। रेल मंत्री अक्षय गिनावरते रहते हैं तो उन्हें कैसे बदला जा सकता है? सार्वजनिक संपत्तियों तो बर्बाद होती रही हैं। ये संपत्तियां कुछ मायनों में महाकुंभ में स्नान करने से भी पवित्र और महत्वपूर्ण हैं। ऐसे तोड़-फोड़ करने और भगदड़ मचाने वाले तत्त्व आध्यात्मिक और आस्थायम नहीं हो सकते। रेल मंत्री अक्षय गिनावरते रहते हैं तो उन्हें कैसे बदला जा सकता है? सार्वजनिक संपत्तियों तो बर्बाद होती रही हैं। ये संपत्तियां कुछ मायनों में महाकुंभ में स्नान करने से भी पवित्र और महत्वपूर्ण हैं। ऐसे तोड़-फोड़ करने और भगदड़ मचाने वाले तत्त्व आध्यात्मिक और आस्थायम नहीं हो सकते। रेल मंत्री अक्षय गिनावरते रहते हैं तो उन्हें कैसे बदला जा सकता है? सार्वजनिक संपत्तियों तो बर्बाद होती रही हैं। ये संपत्तियां कुछ मायनों में महाकुंभ में स्नान करने से भी पवित्र और महत्वपूर्ण हैं। ऐसे तोड़-फोड़ करने और भगदड़ मचाने वाले तत्त्व आध्यात्मिक और आस्थायम नहीं हो सकते। रेल मंत्री अक्षय गिनावरते रहते हैं तो उन्हें कैसे बदला जा सकता है? सार्वजनिक संपत्तियों तो बर्बाद होती रही हैं। ये संपत्तियां कुछ मायनों में महाकुंभ में स्नान करने से भी पवित्र और महत्वपूर्ण हैं। ऐसे तोड़-फोड़ करने और भगदड़ मचाने वाले तत्त्व आध्यात्मिक और आस्थायम नहीं हो सकते। रेल मंत्री अक्षय गिनावरते रहते हैं तो उन्हें कैसे बदला जा सकता है? सार्वजनिक संपत्तियों तो बर्बाद होती रही हैं। ये संपत्तियां कुछ मायनों में महाकुंभ में स्नान करने से भी पवित्र और महत्वपूर्ण हैं। ऐसे तोड़-फोड़ करने और भगदड़ मचाने वाले तत्त्व आध्यात्मिक और आस्थायम नहीं हो सकते। रेल मंत्री अक्षय गिनावरते रहते हैं तो उन्हें कैसे बदला जा सकता है? सार्वजनिक संपत्तियों तो बर्बाद होती रही हैं। ये संपत्तियां कुछ मायनों में महाकुंभ में स्नान करने से भी पवित्र और महत्वपूर्ण हैं। ऐसे तोड़-फोड़ करने और भगदड़ मचाने वाले तत्त्व आध्यात्मिक और आस्थायम नहीं हो सकते। रेल मंत्री अक्षय गिनावरते रहते हैं तो उन्हें कैसे बदला जा सकता है? सार्वजनिक संपत्तियों तो बर्बाद होती रही हैं। ये संपत्तियां कुछ मायनों में महाकुंभ में स्नान करने से भी पवित्र और महत्वपूर्ण हैं। ऐसे तोड़-फोड़ करने और भगदड़ मचाने वाले तत्त्व आध्यात्मिक और आस्थायम नहीं हो सकते। रेल मंत्री अक्षय गिनावरते रहते हैं तो उन्हें कैसे बदला जा सकता है? सार्वजनिक संपत्तियों तो बर्बाद होती रही हैं। ये संपत्तियां कुछ मायनों में महाकुंभ में स्नान करने से भी पवित्र और महत्वपूर्ण हैं। ऐसे तोड़-फोड़ करने और भगदड़ मचाने वाले तत्त्व आध्यात्मिक और आस्थायम नहीं हो सकते। रेल मंत्री अक्षय गिनावरते रहते हैं तो उन्हें कैसे बदला जा सकता है? सार्वजनिक संपत्तियों तो बर्बाद होती रही हैं। ये संपत्तियां कुछ मायनों में महाकुंभ में स्नान करने से भी पवित्र और महत्वपूर्ण हैं। ऐसे तोड़-फोड़ करने और भगदड़ मचाने वाले तत्त्व आध्यात्मिक और आस्थायम नहीं हो सकते। रेल मंत्री अक्षय गिनावरते रहते हैं तो उन्हें कैसे बदला जा सकता है? सार्वजनिक संपत्तियों तो बर्बाद होती रही हैं। ये

चिकित्सा मंत्री का दावा : भर्ती से इस वर्ष 75 प्रतिशत पदों को भरेंगे

जयपुर (हिस)। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा विभाग में 50 हजार राजपत्रित तथा अराजपत्रित पदों पर भर्ती की जा रही है। इनमें से नर्सिंग अधिकारी, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर के 23 हजार पदों पर भर्ती की जा चुकी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस वर्ष मई-जून तक नई भर्तियों से चिकित्सालयों में 75 प्रतिशत पदों को भर दिया जाएगा। सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बंद पड़ी प्रथम रैंफरल इकाइयों को तथा ट्रोमा सेंटर्स को भी फिर से शुरू किया गया है। प्रदेश की लगभग 85 प्रतिशत प्रथम रैंफरल इकाइयों को आर्थोपिडिक, एनेस्थेसिस्ट एवं बच्चों के डॉक्टर नियुक्त कर दिये गए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि नए स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा स्वास्थ्य केंद्रों के



क्रमोन्नयन की कार्यवाही केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडानुसार की जा रही है। सामान्य क्षेत्र में पांच हजार की आबादी पर तथा पहाड़ी, जनजातीय तथा रेगिस्तानी क्षेत्र में 3000 की आबादी पर उपकेन्द्र खोले जाने का प्रावधान है। सिंह ने कहा कि सामान्य क्षेत्र में 30 हजार तथा जनजाति, रेगिस्तानी क्षेत्रों में 20 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य

केंद्र खोलने का प्रावधान है। इस आधार पर पंचायत समिति केशोरायपटन में सात प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की आवश्यकता के विरुद्ध आठ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत हैं। इस कारण यहां उप स्वास्थ्य केंद्र लवान को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाना विचाराधीन नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता तथा गुणावगुण के आधार पर उप स्वास्थ्य केंद्र पीपल्स, जैतपुरा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने पर विचार जाएगा। विधायक चुनीलाल सीएल प्रेमी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश में चिकित्सा केंद्रों को क्रमोन्नत करने के नियम व मानदंड प्रस्तुत किए। सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदंडानुसार एक लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का प्रावधान है।

सैन्य स्टेशन में सैन्य परंपराओं के साथ दक्षिण पश्चिमी कमान अलंकरण समारोह आयोजित



कोटा (हिस)। दक्षिण पश्चिमी कमान अलंकरण समारोह गुरुवार को कोटा सैन्य स्टेशन के गांडी ऑडिटोरियम में पारंपरिक उत्साह और सैन्य भव्यता के साथ आयोजित किया गया। जन संपर्क अधिकारी (रक्षा) जयपुर अरुण अमिताभ शर्मा के अनुसार, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, आर्मी कमांडर दक्षिण पश्चिमी कमान की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल नागेन्द्र सिंह, कोर कमांडर, चेतक कोर द्वारा वीरता और सेवा के लिए कुल 14 पदक प्रदान किए गए। इनमें सात सेना मेडल (वीरता), एक युद्ध सेवा मेडल, एक सेना मेडल (विशिष्ट) और पांच विशिष्ट सेवा मेडल शामिल हैं। यह अलंकरण समारोह वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है, जिसमें असाधारण वीरता और कर्तव्य के प्रति समर्पण दिखाने वाले सैन्य कर्मियों को सम्मानित किया जाता है। इस बार सम्मान पाने वालों में दस अधिकारी, एक जूनियर कमीशन

अधिकारी और तीन सैनिक शामिल थे। व्यक्तिगत पदकों के अलावा, 16 सैन्य यूनिटों को जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ दक्षिण पश्चिमी कमान यूनिट प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे सभी पुरस्कार विजेताओं को उनकी वीरता और राष्ट्र के प्रति विशिष्ट सेवा के लिए बधाई दी। उन्होंने सेना के सभी रैंकों, दिग्गजों और उनके परिवारों से राष्ट्र के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को बनाए रखने का आह्वान किया। समारोह में पुरस्कार विजेताओं के गौरवशाली परिवार भी उपस्थित रहे, जिनका बलिदान और समर्थन भारतीय सेना की वीरता और समर्पण की स्थायी विरासत का आधार बना हुआ है। बाद में पुरस्कार विजेताओं और उनके परिवारों से बातचीत के दौरान मुख्य अतिथि ने भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपराओं को बनाए रखने में उनके योगदान की सराहना की।

दिल्ली से अंबाला तक होगा रेलवे कॉरिडोर का विस्तार : उपायुक्त



सचिवालय में गुरुवार को बैठक की। उपायुक्त ने बताया कि दिल्ली से अंबाला तक के रेलवे कॉरिडोर को फॉरलेन किया जाएगा जो वर्तमान में दो लाईन हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली से अंबाला के बीच स्थित 32 स्टेशनों पर कार्य किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर कुल 7 हजार 74 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो अगले चार साल में पूरा होगा। उपायुक्त ने रेलवे अधिकारियों के समक्ष प्रस्ताव रखा कि इस रेलवे लाईन पर स्थित रेलवे अंडरपास को बजाय रेलवे प्लान्ट/ओवर बनाए जाएं, क्योंकि बारिश के समय अंडरपास में पानी भर जाता है जिसके कारण लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। नगर निगम आयुक्त हर्षित, एसडीएम गोहाना अंजलि श्रीत्रिय, एसडीएम डॉ. निर्मल नागर, एसडीएम सुभाष चंद्र, एसडीएम प्रवेश कसीप, नगार्धोषा डॉ. अनमोल, एसीपी राहुल देव व मलकित सिंह सहित रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे।

जिला शिक्षा पदाधिकारी ने भाजपा विधायक पर लगाया धमकाने का आरोप

पटना (हिस)। बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के पार विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक अशोक सिंह पर जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) ने धमकाने का आरोप लगाया है। डीईओ ने इसकी लिखित शिकायत जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन से की है। इस मामले में पार विधानसभा क्षेत्र के विधायक अशोक सिंह से फोन पर हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र के लोग शिक्षा विभाग में ठेकेदारी किए हैं। लाखों रुपए लोग अपना लगाकर बैठे हैं किसी को पेमेंट नहीं मिल रहा है। इस बात को लेकर पूर्व में मेरे द्वारा मुजफ्फरपुर डीएम को शिकायत की गई थी तो डीएम साहब ने भी फोन कर जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा था कि पेमेंट समय से सबका कर दीजिए। लेकिन उसके बाद भी जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा कोई पहल नहीं किया गया। जिसके बाद पुनः कई दिन बीतने पर हमने जब कॉल किया तो जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि पेमेंट हम नहीं करेंगे हमको डीएम से लिखित दिलवा दीजिए तब पेमेंट करेंगे विधायक अशोक सिंह ने बताया कि हमने यह कहा है कि लगातार शिक्षक से लेकर ठेकेदार और आम जनता आपसे परेशान हैं। कुपया कर अपना तबादला अन्य जिला में कर लीजिए। मुजफ्फरपुर को छोड़ दीजिए। यही बात हमने कही है। किसी

प्रकार की कोई धमकी देने की बात नहीं है। यह जिला शिक्षा पदाधिकारी भ्रष्ट है। हम इसकी शिकायत लिखित में विधानसभा तक पहुंचाएंगे। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए आज तक ऐसा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर में कई ठम से हम विधायक हैं लेकिन देख नहीं है। बिना पैसा का कोई काम ही नहीं करता है और हमारी सरकार के बदनामी होती है। ऐसे लोगों के खिलाफ हमेशा हम विरोध करते हैं और करेंगे अगर हमारी जनता जो हमें वर्षों से विधायक की कुर्सी पर बैठ कर रखा है उसे दिक्कत होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। विधायक अशोक सिंह ने कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को जहां लिखित शिकायत देना हो दे। हमने जो कहा है वह बता दिया है। यह शिक्षा पदाधिकारी ऐसा है जो अपने जिला के जिलाधिकारी की बात नहीं मानता है हम लोग तो विधायक हैं। अशोक सिंह ने बातचीत में कहा इससे या साफ प्रतीत होता है कि पदाधिकारी अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। अब देखा होगा कि जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी के बीच छिड़े विवाद में निष्कर्ष क्या निकलता है। फिलहाल भाजपा विधायक अशोक सिंह ने यह साफ कर दिया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है करवाई कराकर ही रहेंगे।

ट्रक और कार की भिड़ंत में

दादा, बहू और पोते की मौत करौली (हिस)। हिंडौन सिटी-महुवा मार्ग पर देवलन मोड़ के पास बुधवार रात एक ट्रक और स्विफ्ट डिजायर कार की आमने-सामने भिड़ंत में सेना से रिटायर्ड हवलदार, उनकी बहू और पोते की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए और तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। नई मंडी थाना प्रभारी कुलदीप चारण के अनुसार, बाबूलाल गुर्जर (73) अपनी बहू रोशना (30) और पोते रियांश (1) के साथ महुवा में डॉक्टर को दिखाकर अपने गांव तिषरिया (हिंडौन) लौट रहे थे। देवलन मोड़ के पास अचानक सामने आए तेज रफार ट्रक से उनकी कार टकरा गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। परिजनों के अनुसार, रियांश को सर्दी-जुकाम और बुखार था, जिसके इलाज के लिए वे महुवा गए थे। लौटते समय हादसा हो गया। इस दुर्घटना से परिवार में मातम पसर गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है।

गोरखपुर को मिलेगा हाईटेक एयरपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी करेंगे भव्य शिलान्यास



गोरखपुर (हिस)। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2025-26 के बजट में गोरखपुर को बड़ी सीमागत देते हुए अत्याधुनिक एयरपोर्ट के निर्माण की घोषणा की है। 1172 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस हाईटेक एयरपोर्ट को पहले ही पूर्वांचल मंत्रालय की स्वीकृति मिल चुकी है। इस भव्य परियोजना का शिलान्यास मार्च में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। यह नया एयरपोर्ट गोरखपुर को उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों की श्रेणी में लाने के साथ ही क्षेत्रीय विकास को भी नई गति देगा। गोरखपुर एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। 50,000 वर्ग मीटर (13 एकड़) में फैली इस भव्य इमारत में एक घंटे में 2,500 यात्रियों को संभालने की क्षमता होगी। टर्मिनल में यात्रियों को सुविधा को प्राथमिकता देते हुए स्मार्ट चेक-इन काउंटर, सेल्फ-चेक-इन बूथ, हाई-स्पीड वाई-फाई, मॉडर्न लाज, अत्याधुनिक बैगज हैंडलिंग सिस्टम और प्रीमियम वीआईपी सेक्शन जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक एप्रन का निर्माण किया जाएगा, जो एक समय में

10 विमानों को खड़ा करने की क्षमता रखेगा। यहां बड़े विमानों, विशेषकर एयरबस-321 के पाकिंग की भी विशेष व्यवस्था होगी। दिल्ली एयरपोर्ट की तर्ज पर यहां पाँच ऐसे ब्रिज बनाए जाएंगे, जिससे यात्री सीधे टर्मिनल से विमान तक पहुंच सकेंगे। 1200 गाड़ियों के लिए विशाल पार्किंग सुविधा विकसित की जा रही है। वहीं, नंदानगर चौकी से एयरपोर्ट तक 1.5 किलोमीटर लंबी फॉरलेन सड़क बनाई जाएगी, जिससे यात्रियों को एयरपोर्ट तक पहुंचने में कोई असुविधा न हो। सुरक्षा के लिहाज से भी यह एयरपोर्ट अत्याधुनिक होगा। इसमें बायोमेट्रिक एंटी सिस्टम, 24x7 सीसीटीवी निगरानी, डिजिटल इफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम और स्मार्ट बैगज स्कैनिंग जैसी सुविधाएं होंगी। इस एयरपोर्ट के निर्माण से गोरखपुर और पूरे पूर्वांचल की कनेक्टिविटी को एक नई ऊंचाई मिलेगी। यह एयरपोर्ट न केवल गोरखपुर बल्कि आस-पास के जिलों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। इससे व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक विकास को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना के पूरा

होने के बाद गोरखपुर की हवाई यात्रा सुविधाएं दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु और अन्य महानगरों से बेहतर रूप से जुड़ जाएंगी। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए भी इस एयरपोर्ट को विकसित करने की योजना है, जिससे विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों को बेहतरनी सुविधाएं मिल सकें। सरकार इस परियोजना को क्षेत्रीय संतुलन और आधारभूत संरचना को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्राथमिकता दे रही है। गोरखपुरवासियों के लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर है, जो शहर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाने में सहायक होगा। गोरखपुर एयरपोर्ट का विस्तारिकरण शहर के व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों को मजबूती प्रदान करेगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संभावनाओं के साथ, यह परियोजना रोजगार और निवेश के नए अवसर भी खोलेंगी। गोरखपुर का यह हाईटेक एयरपोर्ट न सिर्फ शहर को उड़ान भरने में मदद करेगा, बल्कि इसे विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जल्द ही गोरखपुर को आधुनिक हवाई यात्रा की बेहतरनी सुविधाएं मिलेंगी, जिससे यह शहर एक नए युग में प्रवेश करेगा।

सरकार ने फोन टैपिंग के आरोपों पर दिया जवाब, कांग्रेस ने किया वॉकआउट

जयपुर (हिस)। विधानसभा में गुरुवार को सरकार ने मंत्री किरोड़ी लाल मोणा के फोन टैपिंग के आरोपों पर जवाब दिया। गृह मंत्री जवाहर सिंह बेदम ने सदन में स्पष्ट किया कि किरोड़ी लाल मोणा सहित किसी भी व्यक्ति का फोन टैप नहीं किया गया। सरकार के जवाब पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब सरकार यह मान रही है कि किरोड़ी का फोन टैप नहीं हुआ, तो उनके आरोपों पर क्या कार्यवाही की जाएगी? उन्होंने पूछा कि यदि आरोप झूठे हैं, तो किरोड़ी का इस्तीफा क्यों स्वीकार नहीं किया गया? इस दौरान वन मंत्री संजय शर्मा ने सदन में एक पोस्टर लहरा दिया, जिस पर नेता प्रतिपक्ष जूली ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कोई मंत्री इस तरह से पोस्टर कैसे लहरा सकता है? इस पर सदन में हंगामा हुआ। जूली ने कहा कि मंत्री ने यह जवाब पहले ही दे दिया होता, तो विवाद ही नहीं होता। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के ही कई लोग नहीं चाहते थे कि मुख्यमंत्री का जवाब सुचारु रूप से दिया जाए। फोन टैपिंग के मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। गृह राज्य मंत्री जवाहर

सिंह बेदम ने सदन को आश्चर्य किया कि वर्तमान सरकार की ओर से कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मोणा का फोन इंटरसेप्ट नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वयं किरोड़ी लाल मोणा भी इस बात का सार्वजनिक रूप से खंडन कर चुके हैं। बेदम ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के टेली कम्युनिकेशन अधिनियमों के तहत टेलीफोन इंटरसेप्शन की अनुमति केवल राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने और अपराध रोकने जैसे अति महत्वपूर्ण कार्यों के लिए दी जाती है। उन्होंने बताया कि राज्य में टेलीफोन इंटरसेप्शन की प्रक्रिया गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अनुमति से होती है, जिनके आदेशानुसार ही अधिकृत पुलिस अधिकारियों द्वारा आवश्यक मापदंडों को पूरा करने वाले प्रस्तावों के आधार पर इंटरसेप्शन किया जा सकता है। इसके अलावा, ऐसे इंटरसेप्शन आदेशों की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) और प्रमुख शासन सचिव (विधि एवं विधिक कार्य) सदस्य हैं। समीक्षा समिति की बैठक हर दो माह में एक बार आयोजित करने का प्रावधान है।

राष्ट्रपति अवाड़ी एवं मैडल धारकों को लॉटरी से आवंटित किए जाएंगे भूखंड

जयपुर (हिस)। जेडीसी आनंदी की अध्यक्षता में जेडीए की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तराण समिति की 207वाँ बैठक चित्तौड़ सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड के परिसर के लिए जेडीए की कॉमर्सियल एवं 'रूप हाउसिंग' योजना जनतपुरा में भूखंड संख्या-8ए क्षेत्रफल 1352.70 वर्गमीटर भूमि आवंटन का प्रस्ताव अनुमोदित कर राज्य सरकार की स्वीकृति के लिए भिजवाए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में 19वाँ एशियन गेम विजेता-2022

(चार मेडल धारक), शौर्य चक्र विजेता-2021 (दो मेडल धारक), वीर चक्र विजेता (एक मेडल धारक), राष्ट्रपति पुरस्कार-2015 (दो अवाड़ी), कैलेंड्री अवाड़ी विजेता (दो मेडल धारक), पैरा ओलम्पिक खेल-2020 एवं अर्जुन अवाड़ी-2019 (एक मेडल धारक) को गोविन्द विहार आवासीय योजना में 216 वर्गमीटर के आवासीय भूखंड लॉटरी के माध्यम से प्रत्येक अवाड़ीधारकों को एक-एक भूखंड आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

पीठासीन अधिकारियों को दिया गया चुनाव के पहले चरण का प्रशिक्षण

गुरुग्राम (हिस)। जिला में निकाय चुनाव 2025 को लेकर गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अजय कुमार के मार्गदर्शन में गुरुवार को सेक्टर-14 स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में पीठासीन अधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण सत्र शुरू किया गया। इस दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला में निकाय चुनाव में चुनावी ड्यूटी निभाने वाले पीठासीन अधिकारियों को चार अलग शिप्ट में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अजय कुमार ने पीठासीन अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि मतदान केंद्रों पर मतदान करवाने का कार्य पूरी जिम्मेदारी वाला होता है, इसमें लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव की ड्यूटी को गर्व की अनुभूति के साथ करें। विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र में चुनाव को सुचारु



रूप से संपन्न करवाना हर एक अधिकारी या कर्मचारी की बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा किसी भी तरह का संशय होने पर उच्च अधिकारी से मार्गदर्शन लेकर उसे दूर कर लें। उन्होंने आश्चर्य किया कि चुनाव में ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों तथा अधिकारियों को जिला प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग दिया

राजस्थान में 73 लाख 82 हजार महिलाएं उज्वला योजना से लाभान्वित

जयपुर (हिस)। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि देश की गरीब महिलाओं को पारंपरिक चूल्हों से निकलने वाले जहरीले धुएँ से मुक्ति दिलाने के लिए वर्ष 2016 में उज्वला योजना प्रारंभ की गई थी। योजना के तहत राज्य में जारी कुल एक करोड़ 83 लाख 68 हजार एलपीजी गैस कनेक्शन में से 73 लाख 82 हजार महिलाओं को उज्वला योजना का लाभ दिया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि उज्वला योजना की शुरुआत में देश में पांच करोड़ कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था। वर्तमान में इस योजना के माध्यम से 10 करोड़ 33 लाख एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं। यह उपलब्धि सरकार की प्रतिबद्धता और योजना की सफलता को दर्शाती है, जिससे लाखों गरीब परिवारों को स्वच्छ और सुशिक्षित ईंधन का लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि गंगापुर विधानसभा क्षेत्र में 550 आवेदन लंबित हैं। विधायक रामकेश के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र गंगापुर में वीते एक वर्ष में उज्वला योजना के अंतर्गत कुल एक हजार 668 गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। प्रदेश में उज्वला योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले कनेक्शनों का लक्ष्य पूरा होने के कारण वर्तमान में नए उज्वला कनेक्शन जारी नहीं किए जा रहे हैं।

प्रदेश सरकार का प्रस्तुत बजट शिक्षा व्यवस्था में लगाएगा चार चांद : डॉ. दिवाकर मिश्रा



कानपुर (हिस)। उत्तर प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को प्रस्तुत कुल बजट का 13 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने की घोषणा वित्त मंत्री सुरेश कुमार द्वारा की गई। यह शिक्षा पर खर्च किए जाने वाला सर्वाधिक बजट है। जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। इससे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में चार चांद लगेंगे। यह बजट शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। यह चांदे गुरुवार को डॉ. दिवाकर मिश्रा ने कही उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार उभरने राज्य विधानसभा में

गुरुवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। जो चालू वित्त वर्ष 2024-25 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है। जिससे लेकर अब लोगों की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। इसी क्रम में बीएनएसडी इंटर कॉलेज के प्रवक्ता राष्ट्रपति एवं रजमपाल पुरस्कार से सम्मानित डॉ. दिवाकर मिश्रा ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रस्तुत बजट का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में पहली बार कुल बजट का 13 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। इस बजट में चार सौ करोड़ रुपए की स्कुटी का वितरण मेधावी छात्रों को किया जाएगा। स्कुटी वितरण योजना का नाम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अदम्य साहस का परिचय देने वाली रानी लक्ष्मीबाई पर रखा गया है।

मैट्रिक की परीक्षा में चौथे दिन 586 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित



फारबिसगंज/अररिया (हिस)। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक वार्षिक परीक्षा के चौथे दिनप्रथम पाली में 273 और दूसरी पाली में 313 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। जिलान्तर्गत 43 केंद्रों पर परीक्षा कदाचार मुक्त एवं शान्तिपूर्ण वातावरण में कराए जाने का दावा जिला प्रशासन ने की है। प्रथम पाली

में 14819 परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि 273 परीक्षार्थी अनुपस्थित थे। इसी प्रकार द्वितीय पाली में 14734 उपस्थित एवं 313 परीक्षार्थी अनुपस्थित थे। मैट्रिक वार्षिक (सैद्धांतिक) परीक्षा 17 फरवरी से प्रारंभ होकर 25 फरवरी 2025 तक संचालित होगी। प्रथम पाली की परीक्षा 09-30 बजे पूर्वाह्न से 12-

45 बजे अपराह्न तक तथा द्वितीय पाली की परीक्षा 02:00 बजे अपराह्न से 05-15 बजे अपराह्न तक चलेगी। परीक्षा को लेकर अररिया जिलान्तर्गत (अररियाअनुमंडल) जिला मुख्यालय में 23 परीक्षा केंद्र एवं फारबिसगंज अनुमंडल मुख्यालय में 20 परीक्षा केंद्र, कुल-43 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।



सोने के भाव में तेजी, चांदी की कीमत में भी उछाल, सोना 86,500 रुपए, चांदी भी लगभग 97,000 रुपए

नई दिल्ली सोने और चांदी के वायदा कारोबार में गुरुवार को तेजी देखी जा रही है। गुरुवार को दोनों के वायदा भाव तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। इस समय सोने के वायदा भाव 86,500 रुपये के करीब, जबकि चांदी के वायदा भाव 97,000 रुपये के करीब कारोबार कर रहे थे।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने-चांदी के वायदा भाव में तेजी देखने को मिल रही है। सोने के वायदा भाव की शुरुआत तेजी के साथ

हुई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का बेंचमार्क अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 510 रुपये की तेजी के साथ 86,420 रुपये के भाव पर खुला। इस समय यह कॉन्ट्रैक्ट 578 रुपये की तेजी के साथ 86,488 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था।

इस समय इसने 86,488 रुपये के भाव पर दिन का उच्च और 86,411 रुपये के भाव पर दिन का निचला स्तर छू लिया। सोने के वायदा भाव ने इसी महीने 86,592 रुपये के भाव पर सर्वोच्च स्तर छू लिया था। चांदी के वायदा

भाव की शुरुआत तेज रही। एमसीएक्स पर चांदी का बेंचमार्क मार्च कॉन्ट्रैक्ट 391 रुपये की तेजी के साथ 96,797 रुपये पर खुला। इस समय यह 631 रुपये की तेजी के साथ 97,037 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। इस समय इसने 97,194 रुपये के भाव पर दिन का उच्च और 96,797 रुपये के भाव पर दिन का निचला स्तर छू लिया। पिछले साल चांदी के वायदा भाव ने 1,00081 रुपये किलो के भाव पर सर्वोच्च स्तर छू लिया था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने व चांदी के वायदा भाव तेजी के

साथ कारोबार कर रहे हैं। कॉम्बेक्स पर सोना 2,949.50 डॉलर प्रति औंस के भाव पर खुला। पिछला बंद भाव 2,936.10 डॉलर प्रति औंस था। हालांकि इस समय यह 21.80 डॉलर की तेजी के साथ 2,957.90 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था। कॉम्बेक्स पर चांदी के वायदा भाव 33.15 डॉलर के भाव पर खुले, पिछला बंद भाव 33.04 डॉलर था। इस समय यह 0.24 डॉलर की तेजी के साथ 33.28 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था।

न्यूज़ ब्रीफ

सेबी ने न्युयुअल फंड के नियमों में सुधार किया, एनएफओ में जुटाई गई रकम का निवेश करना होगा

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में हलचल मच गई है जब भारतीय मार्केट रेगुलेटर सेबी ने न्युयुअल फंड के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए नियमों के अनुसार, अब एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को न्यू फंड ऑफर (एनएफओ) में आई रकम को तय समय सीमा में निवेश करना होगा। इसके अलावा सेबी ने न्युयुअल फंड स्कीम के लिए स्ट्रेस टेस्टिंग को अनिवार्य कर दिया है ताकि निवेशकों को स्कीम की वित्तीय स्थिरता को बेहतर समझने में मदद मिले। नए नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे और इनका मकसद न्युयुअल फंड्स के ऑपरेशन को ज्यादा प्रलेक्सिबल और जवाबदेह बनाना है। अप्रैल की पहली तारीख से लागू होने वाले नियमों के अनुसार एनएफओ में न्यू फंड ऑफर से आई रकम को 30 दिनों के अंदर निवेश करना होगा। इससे निवेशकों को भी लाभ होगा क्योंकि अब वे बिना किसी एपिजेंट लोड के अपना पैसा निकाल सकेंगे। इस नए नियम का उद्देश्य एनएफओ को जरूरत से ज्यादा फंड न जुटाने और स्ट्रेस टेस्टिंग के जरिए निवेशकों को स्कीम की वित्तीय स्थिरता को समझने में मदद मिले।

बुलेट और वलासिक 350 ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई



नई दिल्ली। रॉयल एनफील्ड की बुलेट और वलासिक 350 ने भारतीय बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। अब होडा ने अपनी नई बाइक, होडा सीबी 350, के जरिए रॉयल एनफील्ड को चुनौती देने के लिए कदम बढ़ाया है। होडा ने इस बाइक में कई एडवांस फीचर्स भी दिए हैं, जैसे ब्लूटूथ सपोर्ट के साथ होडा स्मार्टफोन वॉयस कंट्रोल सिस्टम, ड्यूल-चैनल एबीएस, 18-इंच व्हील्स, और एलईडी लाइटिंग। बाइक का सेमी-डिजिटल इंस्ट्रुमेंटेशन और डबल लेयर एर्गोनॉमिक्स इसे और भी बेहतर बनाते हैं। होडा सीबी350 को दो वैरिएंट्स में लॉन्च किया गया है - डिलक्स और डिलक्स प्रो। इनकी एक्स-शोरूम कीमतें क्रमशः 1,99,900 और 2,17,800 रुपये हैं। रॉयल एनफील्ड वलासिक 350 के मुकाबले, जो रुपये 1.93 लाख रुपये से शुरू होती है, होडा ने इस बाइक को बेहतर कीमत में पेश किया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि होडा की यह बाइक रॉयल एनफील्ड वलासिक 350 के मुकाबले कैसे प्रदर्शन करती है। यह बाइक न केवल अपने शानदार लुक और डिजाइन के लिए जानी जा रही है, बल्कि इसमें दमदार 350 सीसी इंजन भी दिया गया है, जो इसे वलासिक बाइक प्रेमियों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है। होडा सीबी 350 में 348.36सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 20.8 बौपपी की पावर और 29.4 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ स्लिपर और असिस्ट वलव की सुविधा भी दी गई है। इसके अलावा, बाइक का साइलेंसर नोट रॉयल एनफील्ड वलासिक 350 जैसी आवाज देने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे यह और भी आकर्षक बनती है।

नागरिक उड़ान मंत्री ने पायलटों के लिए लॉन्च किया 'इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस'



नई दिल्ली। केंद्रीय नागरिक उड़ान मंत्री के. राममोहन नायडू ने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित उड़ान भवन में पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कामिक लाइसेंस (ईपीएल) लॉन्च किया। इसके साथ ही भारत चालक दल के सदस्यों के लिए ईपीएल लागू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। चीन पहले ही एपीएल लागू कर चुका है। इस अवसर पर के. राममोहन नायडू ने कहा कि भारत पायलट लाइसेंस को डिजिटल बनाने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। अब हमारे पायलट वैश्विक एजेंसियों के लिए सहज वास्तविक समय सत्यापन के साथ ईजीसीए एप के माध्यम से किसी भी समय अपने लाइसेंस को सुरक्षित रूप से एक्सेस कर सकते हैं। यह भारतीय विमानन के लिए एक बड़ा बदलाव है। नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की ओर से इलेक्ट्रॉनिक कामिक लाइसेंस (ईपीएल) का कार्यान्वयन सरकार की व्यापार सुगमता और डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप है।

प्योर ईवी और जियो थिंग्स के मध्य हुआ समझौता

नई दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता प्योर ईवी कंपनी ने अपने वाहनों में स्मार्ट डिजिटल वलस्टेर और टेलीमैटिक्स को एकीकृत करने के लिए जियो थिंग्स लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत प्योर ईवी अपने इलेक्ट्रिक वाहनों में जियो थिंग्स के स्मार्ट डिजिटल वलस्टेर का उपयोग करेगा, जो एंड-टू-एंड आईओटी समाधान प्रदान करेगा, जिससे उनके वाहनों की कार्यक्षमता और इंटरएक्टिविटी को बढ़ाया जा सकेगा। जियो थिंग्स द्वारा प्रदान की जाने वाली 4जी कनेक्टिविटी और टेलीमैटिक्स की मदद से ग्राहक अपने वाहन के प्रदर्शन की वास्तविक समय में निगरानी कर सकेंगे और संचालन को और अधिक कुशल बना सकेंगे।

इसके अलावा, जियोथिंग्स स्मार्ट डिजिटल वलस्टेर में फुल एचडी प्लस टचस्क्रीन डिस्प्ले कम्पैटिबिलिटी, रीयल-टाइम डेटा एनालिटिक्स और कस्टमाइज्ड टू-व्हीलर इंटरफेस जैसी सुविधाएं शामिल हैं। यह समाधान वाहन निर्माताओं को अपने उत्पादों में आईओटी तकनीकों के एकीकरण में मदद करेगा, जिससे वे उन्नत डिजिटल अनुभव प्रदान कर सकेंगे। प्योर ईवी के संस्थापक और एमडी डॉ. निशांत डोंगरी ने कहा, यह साझेदारी हमारे उत्पादों को उच्चतम मानकों तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। हमारा लक्ष्य इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में दक्षता और इंटरएक्टिविटी को बढ़ाना है।

जियो थिंग्स के अध्यक्ष आशीष लोढ़ा ने इस साझेदारी को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर क्षेत्र के भविष्य को आकार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि इस साझेदारी से ग्राहकों को बेहतर कनेक्टिविटी और कार्यक्षमता का अनुभव मिलेगा। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाना है, जिसमें उन्नत आईओटी समाधान, निम्नलिखित कनेक्टिविटी और डिजिटल एकीकरण का लाभ उठाया जाएगा।

जियो थिंग्स के अध्यक्ष आशीष लोढ़ा ने इस साझेदारी को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर क्षेत्र के भविष्य को आकार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि इस साझेदारी से ग्राहकों को बेहतर कनेक्टिविटी और कार्यक्षमता का अनुभव मिलेगा। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाना है, जिसमें उन्नत आईओटी समाधान, निम्नलिखित कनेक्टिविटी और डिजिटल एकीकरण का लाभ उठाया जाएगा।

अप्रिलिया टूनी 457 स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च
APRILIA TUONO 457
ALL YOU NEED TO KNOW

स्पोर्ट्स बाइक अप्रिलिया टूनी 457 भारत में लॉन्च हो चुकी है। इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 3.95 लाख रुपये रखी गई है। इस बाइक में बाइ-डायरेक्शनल क्लिपऑन और ऑफशन भी है, जो राइडिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाते हैं। टूनी 457 का डिजाइन आरएस 457 से थोड़ा अलग है, इसमें एक नई छोटी एलईडी हेडलाइट है जिसमें दो शाप 3-टाइम रनिंग लाइट्स दी गई हैं। फ्यूल टैंक की क्षमता भी थोड़ी कम है, टूनी में 12.7 लीटर का टैंक दिया गया है, जबकि आरएस 457 में 13 लीटर का टैंक है। इसके बावजूद दोनों बाइक्स का वजन समान, यानी 175 किलोग्राम है। टूनी 457 में छोटी गियरिंग भी दी गई है, जो इसे और भी स्पोर्टी बनाती है। बाइक की बुकिंग शुरू हो गई है, और इसकी डिलीवरी मार्च तक शुरू होने की संभावना है। इस बाइक की कीमत 3.95 लाख रुपये है, जो आरएस 457 से 25,000 रुपये सस्ती है। इसकी टक्कर यामाहा एमटी-03 और कैटीएम 390 ड्यूक जैसी बाइक्स से होगी।

देश में अनेक कंपनियों ने 1 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य का जादुई आंकड़ा पार कर यूनिफॉर्म बनने का तमगा हासिल किया है। लेकिन शुरुआत में इस उपलब्धि को पाने के लिए उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ा। वर्ष 2019 तक जो कंपनियां यूनिफॉर्म बनीं, उन्हें यहाँ तक पहुँचने में औसतन 10 वर्ष लग गए लेकिन केवल चार साल बाद 2023 में यह आंकड़ा पार करने में औसत अवधि पाँच वर्ष ही रही। एक शोध एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि वेंचर कैपिटल (वीसी) और प्राइवेट इन्फ्रस्ट्रक्चर (पीई) ने लाभप्रदता की ज्यादा चिंता किए बिना अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए इन कंपनियों पर जमकर नकदी का निवेश किया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हो जाती। पिछले कुछ वर्षों से जैसे-जैसे इन वीसी और पीई ने निवेश से हाथ खींचना शुरू किया तो स्टार्टअप का यूनिफॉर्म बनने का इंतजार भी लंबा होता गया और 2024 में यूनिफॉर्म का दर्जा पाने का औसत समय बढ़कर पुनः साढ़े नौ वर्ष हो गया और यह



मार्फुति सुजुकी 7 सीटर लेआउट वाली ग्रैंडविटारा का बड़ा वर्जन लाएगी

नई दिल्ली। हाल ही में कार निर्माता कंपनी मार्फुति सुजुकी 7 सीटर लेआउट वाली ग्रैंड विटारा का बड़ा वर्जन भारत में लाने वाली है। हाल ही में, मार्फुति की 7 सीटर एसयूवी को टैस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया, जिसका कोडेनम वाय 17 रखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस नई एसयूवी में 1.5 लीटर की क्षमता वाला नेचुरल एरिपरेटिड माइलड हाइब्रिड इंजन होगा, जो 103 पीएस की पावर और 136.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। इसके अलावा, स्ट्रॉंग हाइब्रिड इंजन का विकल्प भी मिलेगा, जो 115 पीएस की पावर और 141 न्यूटन मीटर का टॉर्क उत्पन्न करेगा। मार्फुति ने इस नई एसयूवी के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। बाजार में इसका सीधा मुकाबला महिंद्रा स्कोर्पियो, एमजी हेक्टर, टाटा सफारी और हुंडई अल्ट्रजोर जैसी एसयूवी से होगा। ग्रैंड विटारा के आईसीई इंजन वाले मॉडल को भारतीय बाजार में शानदार रियॉन्स मिलता है। कंपनी अब इस कार का इलेक्ट्रिक वर्जन भी लाने वाली है, जो मार्फुति की पहली इलेक्ट्रिक कार होगी। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में एटी के बाद मार्फुति सुजुकी अन्य कंपनियों के लिए नई चुनौती पेश करेगी। बता दें कि मार्फुति सुजुकी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी, मार्फुति सुजुकी ई-विटारा को पेश किया था। इस कार को भारत मोबिलिटी ऑटो एक्सपो में प्रदर्शित किया गया था।



द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का मकसद रखा है। जीटीआरआई के एक अधिकारी ने बताया कि भारत को पेट्रोलसायन और ऊर्जा आयात पर शुल्क रियायतों के संरक्षण का ध्यान देना चाहिए ताकि देश के घरेलू उद्योगों को नुकसान न हो। उन्होंने सावधानी बरतने की सलाह

भारत और कतर के बीच व्यापार समझौते में सावधानी की जरूरत: जीटीआरआई

नई दिल्ली आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनशिएटिव (जीटीआरआई) ने भारत और कतर के बीच संभावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर ध्यान दिलाते हुए कहा है कि पेट्रोलसायन क्षेत्र में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमिम बिन हमद अल-सानी ने जारी संयुक्त बयान के माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौते (सीपीए) में प्रवेश करने के लिए तैयारी दिखाई है।

इसमें उन्होंने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का मकसद रखा है। जीटीआरआई के एक अधिकारी ने बताया कि भारत को पेट्रोलसायन और ऊर्जा आयात पर शुल्क रियायतों के संरक्षण का ध्यान देना चाहिए ताकि देश के घरेलू उद्योगों को नुकसान न हो। उन्होंने सावधानी बरतने की सलाह

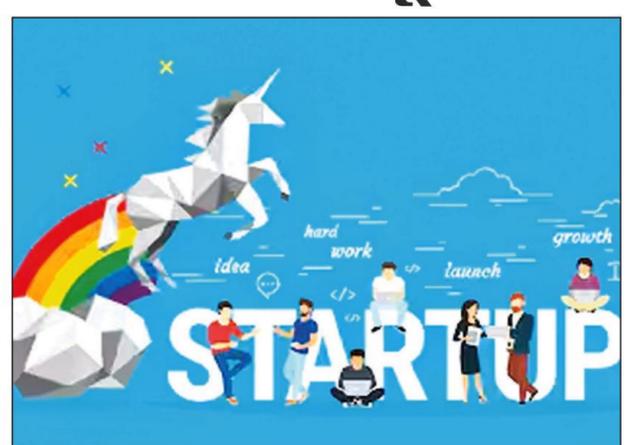


दी और व्यापार समझौते के प्राथमिक शर्तों के मूल्यांकन की मांग की। इस संदर्भ में, भारत के व्यापार संरचना को ध्यान में रखते हुए एक सावधानीपूर्वक मूल्यांकन की आवश्यकता है। वित्त वर्ष 2023-24 में कतर से भारत का आयात 12.34 अरब डॉलर था, जिसे इसके निर्यात के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है। सीपीए के माध्यम से दोनों देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता स्थापित करने का उद्देश्य है जो दोनों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूती प्रदान करेगा। यह एक सकारात्मक कदम है जो व्यापार और आर्थिक उद्वारण में मदद करेगा।

द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का मकसद रखा है। जीटीआरआई के एक अधिकारी ने बताया कि भारत को पेट्रोलसायन और ऊर्जा आयात पर शुल्क रियायतों के संरक्षण का ध्यान देना चाहिए ताकि देश के घरेलू उद्योगों को नुकसान न हो। उन्होंने सावधानी बरतने की सलाह

भारतीय स्टार्टअप के लिए यूनिफॉर्म बनने की अवधि फिर बढ़ी

देश में अनेक कंपनियों ने 1 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य का जादुई आंकड़ा पार कर यूनिफॉर्म बनने का तमगा हासिल किया है। लेकिन शुरुआत में इस उपलब्धि को पाने के लिए उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ा। वर्ष 2019 तक जो कंपनियां यूनिफॉर्म बनीं, उन्हें यहाँ तक पहुँचने में औसतन 10 वर्ष लग गए लेकिन केवल चार साल बाद 2023 में यह आंकड़ा पार करने में औसत अवधि पाँच वर्ष ही रही। एक शोध एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि वेंचर कैपिटल (वीसी) और प्राइवेट इन्फ्रस्ट्रक्चर (पीई) ने लाभप्रदता की ज्यादा चिंता किए बिना अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए इन कंपनियों पर जमकर नकदी का निवेश किया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हो जाती। पिछले कुछ वर्षों से जैसे-जैसे इन वीसी और पीई ने निवेश से हाथ खींचना शुरू किया तो स्टार्टअप का यूनिफॉर्म बनने का इंतजार भी लंबा होता गया और 2024 में यूनिफॉर्म का दर्जा पाने का औसत समय बढ़कर पुनः साढ़े नौ वर्ष हो गया और यह



ट्रंप नहीं चाहते भारत में टेस्ला अपनी फैक्ट्री लगाए, टेस्ला के ग्राहकों पर हो सकता है असर

नई दिल्ली। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ टैरिफ के मुद्दे पर फिर एक बयान दिया है। ट्रंप ने एक टीवी शो में एलन मस्क के साथ साक्षात्कार किया कि उन्हें लगता है कि भारत में इंपोर्ट ड्यूटी बेहद उच्च है और इससे वहाँ उनके कारों की बिक्री पर असर पड़ता है। ट्रंप ने कहा, वे (भारत वाले) इसका उदाहरण है, मुझे नहीं पता ये सच है या नहीं लेकिन यहाँ (भारत में) इंपोर्ट ड्यूटी शायद 100 फीसदी है इस पर मस्क ने स्वीकार किया। ट्रंप ने और भी कहा कि अब अगर वे भारत में फैक्ट्री लगाते हैं तो टीक है लेकिन यह हमारे साथ बहुत बड़ी नईसाझगी होगी। इस बयान से हर भारतीय का मन खड़ा हो गया है। इस बात को लेकर भारत में टेस्ला के ग्राहकों पर भी हो सकता है असर, जिन्होंने उम्मीद रखी थी कि कंपनी भारत में अपनी फैक्ट्री लगाएगी।

अवधि 2019 के स्तर पर पहुँच गई। एक अध्ययन के अनुसार अमेरिका में स्थिति इसके बिल्कुल उल्टा है, जहाँ 2014 के बाद किसी स्टार्टअप को यूनिफॉर्म बनने में 3.4 वर्ष का समय लगा। इससे पहले वहाँ छोटी कंपनियों को इस उपलब्धि तक पहुँचने के लिए 6.6 वर्ष लग जाते थे। वैसे स्टार्टअप की दुनिया एक शोध का विषय रहा है। स्टार्टअप के विकास के लिए 2021 का साल सबसे बेहतर रहा जब कॉन्फिडेंसीएक्स, क्रैड, जेटविक, भारतपे और मोबाइल प्रीमियर लीग जैसे बड़े ब्रांड तीन वर्ष के अंदर ही यूनिफॉर्म बन गए। लेकिन सभी स्टार्टअप को एक जैसी तरकीब का रास्ता नहीं मिला। कुछ ऐसे भी रहे, जिन्होंने यूनिफॉर्म जैसा मील का पत्थर छूने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ा।

द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का मकसद रखा है। जीटीआरआई के एक अधिकारी ने बताया कि भारत को पेट्रोलसायन और ऊर्जा आयात पर शुल्क रियायतों के संरक्षण का ध्यान देना चाहिए ताकि देश के घरेलू उद्योगों को नुकसान न हो। उन्होंने सावधानी बरतने की सलाह



हमें उम्मीद नहीं थी कि न्यूजीलैंड बोर्ड पर 320 रन बनाएगा: मोहम्मद रिजवान

कराची

सात साल के लंबे इंतजार के बाद चैंपियंस ट्रॉफी की वापसी हुई, और टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 60 रनों से हराकर शानदार आगाज किया।

इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की शुरुआत संघर्षपूर्ण रही। पाकिस्तानी गेंदबाजों नसीम शाह, हारिस रऊफ और अब्बास अहमद ने

कड़ा मुकाबला पेश किया और शुरुआती 73 रन के भीतर डेवोन कॉर्नवे, केन विलियमसन और डेरिल मिशेल के विकेट झटक लिए। लेकिन इसके बाद टॉम लेथम (118) और विल यंग (107) ने 118 रनों की साझेदारी कर न्यूजीलैंड को मुश्किल हालात से बाहर निकाला। अंत में ग्लेन फिलिप्स ने 39 गेंदों में 61 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिससे न्यूजीलैंड ने आखिरी 10 ओवरों में 113 रन जोड़कर स्कोर को 320/5 तक पहुंचा दिया।

रिजवान ने मानी डेथ ओवरों में चूक-

लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम इस विशाल लक्ष्य के दबाव में बिखर गई और पूरी टीम 260 रन के भीतर सिमट गई। मैच के बाद पाकिस्तान के बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने कहा, हमें उम्मीद नहीं थी कि वे 320 तक पहुंच जाएंगे। हमने सोचा था कि उन्हें 260 के आसपास रोक लेंगे, लेकिन विल यंग और लेथम ने बहुत समझदारी से खेला। अंतिम ओवरों में हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं था, जिससे उन्होंने बड़ा स्कोर खड़ा कर लिया।

भारत के खिलाफ करो या मरो का

मुकाबला - रविवार को पाकिस्तान का मुकाबला अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी भारत से होगा। इस मैच में हार पाकिस्तान की खिलाड़ी रक्षा की उम्मीदों को खत्म कर सकती है। हालांकि, बढ़ते दबाव के बीच रिजवान ने कहा, हम इस मैच को एक सामान्य मुकाबले की तरह लेंगे और खुद पर गत चैंपियन होने का अतिरिक्त दबाव नहीं डालेंगे। अब सभी की निगाहें भारत-पाकिस्तान के हाई-वोल्टेज मुकाबले पर टिकी हैं, जहां पाकिस्तान को हर हाल में जीत की दरकार होगी।

न्यूज़ ब्रीफ

रेफरी को अपशब्द कहने पर जूड बेलिंगहैम पर लगा दो मैचों का प्रतिबंध



मैड्रिड। स्पेनिश फुटबॉल महासंघ (आरएफईएफ) की अनुशासनात्मक समिति ने रियल मैड्रिड के इंग्लिश मिडफील्डर जूड बेलिंगहैम पर दो मैचों का प्रतिबंध लगाया है। यह कार्रवाई उन्हें ओसासुना के खिलाफ पिछले शनिवार को खेले गए मैच में लाल कार्ड दिखाए जाने के बाद की गई है। मैच के पहले हाफ में रेफरी जोस लुइस मुनुएरा मोटेरो ने बेलिंगहैम को अपशब्द कहने के आरोप में बाहर भेज दिया था। हालांकि, रियल मैड्रिड ने रेफरी की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि बेलिंगहैम ने एफ यू की जगह एफ ऑफ कहा था। आरएफईएफ ने बेलिंगहैम को रेफरी के प्रति अनादर का दोषी पाया है, जिसके चलते उन्हें दो मैचों के लिए निलंबित किया गया। यदि उन्हें रेफरी का अपमान करने का दोषी माना जाता, तो उनका प्रतिबंध 4 से 12 मैचों तक बढ़ सकता था। इस फैसले के बाद रेफरी मुनुएरा को सोशल मीडिया पर धमकियाँ और अभद्र टिप्पणियों का सामना करना पड़ा है। उन्हें और उनके परिवार को निशाना बनाते हुए सैकड़ों अपमानजनक संदेश भेजे गए, जिससे मजबूर होकर उन्होंने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल बंद कर दी है। रियल मैड्रिड बेलिंगहैम के प्रतिबंध के खिलाफ अपील कर सकता है। अगर प्रतिबंध बरकरार रहता है, तो बेलिंगहैम शनिवार को गिरोना और अगले हफ्ते बेटिस के खिलाफ होने वाले मैचों में नहीं खेल पाएंगे।

डिविलियर्स का आरसीबी ने सही तरीके से उपयोग नहीं किया: मांजरेकर

मुम्बई। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर अपने विवादाित बयानों के कारण चर्चाओं में बने रहते हैं। अब उन्होंने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज रहे एबी डिविलियर्स ने आईपीएल में गलत टीम से खेला था।

डिविलियर्स ने शुरुआत में दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए आईपीएल में तीन सत्र खेले थे। वहीं 2011 की आईपीएल मेगा ऑक्शन में वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) में शामिल हुए और 2021 में अपने करियर को अलविदा कहने तक उसकी ओर से ही खेलते रहे। डिविलियर्स ने 184 आईपीएल मैचों में 5162 रन बनाए लेकिन कभी टीम को आईपीएल खिताब नहीं जिता पाये। उन्होंने 2011 और 2016 में आरसीबी के साथ आईपीएल फाइनल खेला पर दोनों बार टीम हार गयी। 14 साल के अपने आईपीएल करियर में खिताब न जीतने के बावजूद डिविलियर्स आईपीएल में खेलने वाले सबसे बड़े क्रिकेटरों में से एक हैं। मांजरेकर के अनुसार डिविलियर्स का आरसीबी ने सही तरीके से उपयोग नहीं किया। मांजरेकर का कहना है कि डिविलियर्स को टॉप आर्डर में आना चाहिए था और उन्होंने यह भी कहा कि एबी ने गलत फ्रेंचाइजी के लिए खेला। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु तीन बार ट्रॉफी के करीब पहुंची, 2009, 2011 और 2016 में, लेकिन वे फाइनल में हार गए। ट्रॉफी के सूखे के बावजूद, आरसीबी अतीत में कई महान बल्लेबाजों का घर रहा है जो मैच विनर से कम नहीं हैं। चाहे वह केपल राहुल हो, शेन वॉटसन हो, क्रिस गेल हो, ब्रेंडन मैकुलम हो या एबी डिविलियर्स, आरसीबी ने हमेशा अपने रैंकों में आक्रामक बल्लेबाजों की विलासिता का आनंद लिया है जो खेल को विषम से दूर ले जा सकते हैं, लेकिन उनका खिताब का सूखा जारी है।

एलएसजी का रुख आईपीएल में आक्रामक रहेगा: जहीर

नई दिल्ली। लखनऊ सुपर जाइंट्स (एलएसजी) टीम के मेंटर जहीर खान ने कहा है कि डिवियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 में लखनऊ सुपरजाइंट्स के पास बाएं हाथ के कई बल्लेबाज हैं। पिछले साल की मेगा नीलामी के दौरान लखनऊ ने पांच बाएं हाथ के बल्लेबाजों को खरीदा है। इसमें से तीन को अंतिम ग्यारह में जगह मिल सकती है। ऋषभ पंत, निकोलस पूरन और डेविड मिलर शुरुआत में उतरेंगे। साथ ही कहा कि तीन बाएं हाथ के बल्लेबाजों के होने से टीम का रुख आक्रामक रहेगा। जहीर के अनुसार इनमें बाएं हाथ के खिलाड़ी रखना टीम की रणनीति भी हो सकती है। एलएसजी ने इस सत्र के लिए ऋषभ को कप्तान बनाया है। 2016 में दिल्ली डेयरडेविल्स की कप्तानी करने वाले जहीर ने ऋषभ को देखा है और उनके साथ काम किया है। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज के अनुसार ऋषभ ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरी टीम को प्रेरित कर सकते हैं और क्रिकेट का एक ऐसा ब्रांड स्थापित कर सकते हैं जिसे एलएसजी खेला चाहता है। उन्होंने कहा कि सीजन में उस माहौल को बनाने और किसी भी टीम के लिए सफलता के स्तंभ तैयार करने के लिए कप्तान की भूमिका अहम होती है।

जिम्मेवर वरुण है। जहीर ने कहा, यह सामरिक बदन भी हो सकती है। हम इसे इसी तरह से देख रहे हैं। मैंने यह नहीं देखा है कि मैं टीम में कितने बाएं हाथ के खिलाड़ियों को चाहता हूँ।

लक्ष्य का पीछा करने में सचिन से विराट को बेहतर मानते हैं सहवाग

नई दिल्ली

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का मानना है कि एकदिवसीय में लक्ष्य का पीछा करने में सचिन तेंदुलकर की तुलना में विराट कोहली बेहतर है। तेंदुलकर को दूसरे नंबर पर रखने पर सहवाग ने कहा कि क्रिकेट जगत एकदिवसीय क्रिकेट में कोहली जैसा निरंतरता वाला खिलाड़ी शायद ही दूसरा देख पाएगा। शुरुआत में, वह वह विराट कोहली नहीं थे जो वह हैं। उन्होंने अपना समय लिया और बहुत कुछ सीखा। और 2011-12 के बाद, वह बहुत बदल गए हैं। अपनी फिटनेस में और अपनी निरंतरता में उन्होंने अद्भुत परिवर्तन देखे हैं।

सहवाग ने ऐसे शीर्ष पांच बल्लेबाजों की सूची में वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज क्रिस गेल को पांचवें नंबर पर रखा है जबकि एकदिवसीय प्रारूप में गेल के 304 मैचों में 10480 रन हैं। उन्होंने कहा कि गेल एक महान बल्लेबाज और सलामी बल्लेबाज थे। मुझे याद है कि भारत 2002-03 में वेस्टइंडीज आया था और क्रिस गेल ने 6 मैचों की श्रृंखला में तीन शतक लगाए थे। वह पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा था जो तेज गेंदबाजों के लिए बैकफुट पर आकर छक्के मारते थे। वहीं नंबर 4 स्थान दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स को दिया गया, जिन्होंने अपने करियर के दौरान 228 एकदिवसीय मैचों में 9577 रन बनाए। उनके बाद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इजमाम-उल-हक हैं जिन्होंने 350 पारियों में 11739 रन बनाए हैं। सहवाग ने कहा कि नंबर 4 पर एबी डिविलियर्स हैं। वह जिस तरह से खेलते थे वह मुझे बहुत पसंद आया। वह एकमात्र बल्लेबाज हैं जो असंतुलित होकर छक्के मार सकते हैं। नंबर 3 पर इजमाम-उल-हक हैं। वह एशिया के सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ियों में से एक हैं। इजमाम नंबर 4 पर बल्लेबाजों करने आते थे और मैच को नियंत्रित करते थे।



नीरज के पास है एक से बढ़कर एक हाई-परफॉर्मिंग लक्जरी कारें

नई दिल्ली। भारत के स्टार बल्लेबाज नीरज चोपड़ा खेल के साथ ही हाई-परफॉर्मिंग लक्जरी कारों के भी शौकीन हैं। नीरज के पास एक से बढ़कर एक कारों का काफिला है। नीरज के इस बेड़े में हाल ही में ऑडी की आरएस व्यू-8 परफॉर्मिंग कार शामिल हुई है। उनके पास पहले से ही मस्टैंग और कई टोयोटा फोर्च्यूनर जैसी कारें हैं। नीरज की आरएस व्यू-8 कार एक हाई-परफॉर्मिंग एसयूवी और पहियों पर चलने वाली एक पावरहाउस है। ये कार 305 किमी/घंटा की टॉप स्पीड के साथ सड़कों पर दौड़ सकती है। वहीं, यह केवल 3.6 सेकेंडों में 0-100 किमी/घंटा की गति पकड़ लेती है। ऑडी की ओर से आने वाली इस कार के बेस मॉडल की कीमत 2.5 करोड़ रुपये है पर कस्टमाइजेशन के बाद, नीरज के वर्जन की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपये है। नीरज ने जो कार डिजाइन कराई है उसमें उनकी पसंद की हर चीज का ध्यान रखा है। अपनी इस नई कार के बारे में बात करते हुए नीरज ने कहा, मुझे कारों बहुत पसंद हैं। कड़ी मेहनत की वजह से ही मैं उन्हें खरीद पाया हूँ। मेरा सपना सच हो गया। मैं और मेरा परिवार एक घर चाहते थे। यह बहुत अच्छी बात है कि अब हमारे पास एक घर है। हमारे सपने हकीकत में बदल रहे हैं। रफतार और लजरी के शौकीन नीरज चोपड़ा के पास महंगी और लजरी गाड़ियों का शानदार कलेक्शन है। इनमें कस्टमाइज्ड महिंद्रा एक्सयूवी 700 शामिल है वहीं उनके पास एक महिंद्रा थार भी है जिसकी कीमत लगभग 17 लाख रुपये है। इनकी सबसे महंगी गाड़ियों में रेंज रोवर शामिल हैं जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपये है। नीरज के पास 33 लाख रुपये की टोयोटा फोर्च्यूनर है। वहीं मस्टैंग जीटी की कीमत 93.52 लाख शामिल है।



कतर ओपन: कार्लोस अलकराज कार्टर फाइनल में पहुंचे, जिरी लेहेका से होगी भिड़ंत



स्पेन के शीर्ष वरिष्ठता प्राप्त कार्लोस अलकराज ने बुधवार को इतालवी कालीफायर लुका नारदी को हराकर कतर ओपन के कार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। हालांकि, यह जीत उनके लिए आसान नहीं रही। पहला सेट जीतने और दूसरे सेट में 4-1 की बढ़त लेने के बावजूद, अलकराज को संघर्ष करना पड़ा जब नारदी ने लगातार पांच गेम जीतकर मैच को निर्णायक सेट तक खींच लिया। तीसरे सेट में, अलकराज ने चौथे गेम में महत्वपूर्ण ब्रेक हासिल किया और 6-1, 4-6, 6-3 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। मैच के बाद अलकराज ने कहा, उन्होंने कुछ शानदार अंक खेले और ऐसा लगने लगा कि वह दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी की तरह खेल रहे हैं। मैं बस खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। तीसरे सेट में वापसी कर जीत हासिल करना मेरे लिए संतोषजनक है।

सीजन के अंत में संन्यास लेंगे एथलेटिक क्लब बिलबाओ के डिफेंडर ऑस्कर डी मार्कोस

मैड्रिड

एथलेटिक क्लब बिलबाओ के अनुभवी डिफेंडर ऑस्कर डी मार्कोस ने बुधवार को घोषणा की कि वह मौजूदा सीजन के अंत में फुटबॉल से संन्यास ले लेंगे। अप्रैल में 36 साल के होने जा रहे डी मार्कोस इस समय क्लब के साथ अपने 16वें सीजन में खेल रहे हैं। पिछले रविवार को एस्पेन्योल के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने 560वां बार क्लब के लिए मैदान पर उतरकर खुद को एथलेटिक के इतिहास में दूसरा सबसे ज्यादा मैच खेलने वाला खिलाड़ी बना लिया। इस सूची में वह इकर मुनिएन के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं, जबकि जोसे एंजेल इरिबार् (614 मैच) इस सूची में शीर्ष पर हैं।

जनवरी में कर लिया था फैसला

डी मार्कोस ने क्लब के लेज़ामा प्रशिक्षण मैदान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि



उन्होंने जनवरी की शुरुआत में कोच अर्नेस्टो वल्बार्डे को अपने संन्यास के फैसले की जानकारी दे दी थी।

उन्होंने कहा, यह फैसला पहले से ही मेरे मन में था, लेकिन बीच-बीच में मैंने जारी रखने के बारे में भी सोचा। हालांकि, इस बार मुझे पूरा यकीन था कि यही सही समय है।

शानदार करियर का समापन

इस सीजन में डी मार्कोस ने ला लीगा में 19 और यूरोपा लीग में छह मुकाबले खेले हैं। उनकी टीम एथलेटिक बिलबाओ इस समय ला लीगा में चौथे स्थान पर बनी हुई है और यूरोपा लीग के अंतिम-16 में भी जगह बना चुकी है।

डी मार्कोस ने कहा, मुझे लगता है कि यह मेरे लिए सही समय है। मैंने यह देखने के लिए इंतजार किया कि मेरा शरीर क्या कहता है, और इसने मुझे संकेत दिया कि अब समय आ गया है। मैं चाहता था कि जब तक खेले, तब तक उपयोगी बना रहूँ,

और मुझे खुशी है कि मैं ऐसा कर पाया।

अलग-अलग भूमिकाओं में चमका करियर ऑस्कर डी मार्कोस ने अपने करियर की शुरुआत एक फॉरवर्ड के रूप में की थी। अपने 16 साल के करियर में वह विंगर और अटैकिंग मिडफील्डर के रूप में भी खेले, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने राइट बैक की भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने क्लब के लिए 39 गोल भी किए।

दान कार्यों में भी रहे सक्रिय

डी मार्कोस न केवल अपने खेल के लिए बल्कि मानवीय कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने स्थानीय अस्पतालों में बच्चों से मुलाकात, और अफ्रीका व लैटिन अमेरिका में चैरिटी यात्राओं जैसी गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लिया। अब, जब वह अपने शानदार करियर को अलविदा कहने की तैयारी कर रहे हैं, तो फुटबॉल जगत में उनकी जगह हमेशा सम्मान के साथ याद की जाएगी।

श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया सीरीज से बाहर हुई न्यूजीलैंड की तेज गेंदबाज मौली पेनफोल्ड



वेलिंग्टन

न्यूजीलैंड की तेज गेंदबाज मौली पेनफोल्ड घुटने की गंभीर चोट के कारण शेष सत्र से बाहर हो गई हैं। इसका मतलब है कि वह श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी श्रृंखला में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। 23 वर्षीय पेनफोल्ड को इस महीने की शुरुआत में हैलीबर्टन जॉर्नस्टोन शील्ड के दौरान बाएं घुटने में मेनिस्कस की चोट लगी थी, जिसके बाद उनकी सर्जरी हुई। उनकी रिकवरी में करीब 12 सप्ताह लगने की उम्मीद है।

मुख्य कोच बेन साँयर ने इस पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा, यह मौली के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, और खासकर रोज बाउल श्रृंखला में उनके प्रभाव प्रदर्शन के बाद। हालांकि,

सकारात्मक बात यह है कि वह शीतकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम तक फिट हो सकती हैं।

पेनफोल्ड ने अब तक 14 वनडे में 9 और 10 टी20 मुकाबलों में 7 विकेट लिए हैं। पिछले साल दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेसिन रिजर्व में उन्होंने 42 रन देकर 4 विकेट झटकें थे, जो उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा।

सोफी ड्रिवाइन भी श्रीलंका के खिलाफ नहीं खेलेंगी

न्यूजीलैंड को श्रीलंका के खिलाफ अपने स्टार खिलाड़ी सोफी ड्रिवाइन के बिना भी उतरना होगा। ड्रिवाइन ने खेल से ब्रेक ले रखा है और उनकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उपलब्धता को लेकर अभी तक पुष्टि नहीं हुई है।

यूपी वॉरियर्स को हराकर दूसरे नंबर पर पहली दिल्ली कैपिटल्स



मुम्बई

दिल्ली कैपिटल्स की टीम महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) में यूपी वॉरियर्स को 7 विकेट से हराकर लीग में दूसरे स्थान पर पहुंच गयी है। वहीं पिछले मैच में उसे आरसीबी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। उसने अब तक तीन मैच से दो मैच जीते हैं। इस सत्र में मिली दूसरी जीत से कैपिटल्स की टीम अंक तालिका में 4 अंकों और नेट रन रेट नेट रन रेट -0.544 के साथ दूसरे स्थान

पर पहुंच गयी है। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) की टीम 4 और नेट रन रेट +1.440 के साथ ही नंबर एक स्थान पर चल रही है। आरसीबी और डीसी दोनों के ही बराबर 4-4 अंक हैं पर बेहतर नेट रन औसत होने के कारण आरसीबी नंबर एक पर जबकि दिल्ली दूसरे स्थान पर है। आरसीबी टूर्नामेंट में अकेली ऐसी टीम है जो अभी तक नहीं हारी है। वहीं मुम्बई इंडियंस 2 अंकों के साथ ही दूसरे नंबर पर है। गुजरात जाएंट्स के भी 2 अंक हैं

और वह चौथे नंबर पर है। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए यूपी वॉरियर्स ने किरण नवगिरे के अर्धशतक से 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 166 रन बनाये। इस स्कोर का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम शैफाली वर्मा 26 और मेग लैंगिंग 69 ने अच्छी शुरुआत देते हुए पहले विकेट के लिए 6.5 ओवर में 65 रन बनाये। इसके बाद एनाबेल सरसेन्ड ने 41 रनों की पारी खेल टीम को 1 गेंद और 7 विकेट शेष रहते जीत दिलाई।

पथरी हो या कैंसर बचाता है बथुआ



सब्जी, रायते व खाने में कई तरह से प्रयोग में लाया जाने वाला बथुआ अनेक औषधीय गुणों से भरपूर है। इसमें शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसे खाने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। पथरी हो या कैंसर सबसे बचाव करता है बथुआ। जानिए इससे होने वाले फायदों के बारे में...

बीमारियों में लाभकारी बथुआ

ब्रेस्ट कैंसर: आयुर्वेद में किए गए शोध के मुताबिक बथुआ को नियमित खाने से ब्रेस्ट कैंसर की आशंका कम हो जाती है। इसमें मौजूद सेलिनियम, ओमेगा-3 व 6 फटी एसिड ब्रेस्ट कैंसररोधक होते हैं।

जोड़ों में दर्द: इसके 10 ग्राम बीजों को करीब 200 मिलीलीटर पानी में उबालें। 50 मिलीलीटर बचने पर गर्मागर्म पीएं। ऐसा एक महीने तक सुबह-शाम करने से जोड़ों के दर्द में लाभ होता है। इसकी ताजी पत्तियों को पीसकर हल्का गर्म करें और दर्द वाले स्थान पर बांधें। इससे भी दर्द में आराम मिलता है।

एनीमिया: इसमें आयरन व फोलिक एसिड होता है। करीब डेढ़ माह तक सजी बनाकर खाने या इसका 15-20 मिलीलीटर (करीब 4 चम्मच) रस सुबह-शाम लेने से खून की कमी की समस्या दूर होती है।

पीलिया: इसके 15 मिलीलीटर रस को 30 मिलीलीटर गिलोय रस के साथ करीब 10 दिनों तक लेने से पीलिया में राहत मिलती है।

बावसीर: इसके पंचांग (तना, जड़, पत्ते, फूल व बीज) को सुखाकर चूर्ण बना लें। करीब 10 ग्राम चूर्ण 15 दिनों तक सुबह-शाम बकरी के दूध के साथ लें, समस्या दूर होगी।

अनियमित माहवारी: 10 ग्राम बीज को 200 मिली पानी में उबालें। 50 मिली बचने पर छान लें। छने हुए पानी में करीब 2 ग्राम सौंठ मिलाकर गर्म-गर्म पीएं। इससे अनियमित माहवारी की समस्या व दर्द में आराम मिलता है।

पथरी: बथुआ में क्षार होता है। पथरी की शुरुआती स्टेज में इसके रस को 20 दिनों तक पीने से पथरी टूटकर यूरिन के जरिए बाहर आ जाती है।

ये टॉयलेट है स्मार्ट, जांच लेता है बीमारी



दुनिया के सबसे बड़े टॉयलेट मैनुफैक्चरर कंपनी टोटो ने एक अलग तरह के टॉयलेट का निर्माण किया, जिसकी खासियतें सुनकर आप चौंक सकते हैं। दरअसल, टॉयलेट मैनुफैक्चरर कंपनी टोटो ने ऐसा टॉयलेट विकसित किया है, जो सेहत के संभावित खतरों के लिए किसी को भी आगाह कर सकता है। टोटो ने अपने इस अनोखे टॉयलेट के बारे में जानकारी जापान के योकोहामा में हुए एम-बायो जापान 2015 कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। डॉक्टर की तरह सेहत के लिए अलर्ट करने वाले टॉयलेट के निर्माण में विशेष तकनीक प्रयोग की गई है। साथ ही इसमें प्रयोग की गई तकनीक को जापान की तेजी से बुजुर्ग होती जनसंख्या के लिए वरदान माना जा रहा है। दरअसल, टोटो कंपनी ने इस फ्लोस्काई नाम के टॉयलेट की खासियत है कि ये यूरिन फ्लो रेट को माप सकता है। इसके लिए इसे खास तरह के सेंसर से लैस किया गया है। ये सेंसर यूरिन के यूरिन फ्लो रेट ही यूरिन के वॉल्यूम परिवर्तन जैसी कई तरह की गणनाएं कर लेते हैं। रीडिंग टॉयलेट से रीलीव होने के फौरन बाद मिल जाती है। ये तकनीक उन मरीजों के लिए बहुत लाभदायक है जो दूरदराज के इलाकों में रहते हैं। इन मरीजों से दूर बैठा डॉक्टर उनके स्वास्थ्य पर इस एप्लीकेशन के जरिए नजर रख सकता है।

यहां नलों से गिरती है शराब



स्पेन में ईराक और एस्टेला ऐसी चर्चित जगह है, जहां पर शराब के गोदामों को देखकर और शराब से जुड़ी कई अलग तरह की बातें जानकर कोई भी व्यक्ति हैरान हो जाता है। यहाँ पर शराब से जुड़े कई किस्से सुनने को मिलते हैं, जिनमें से एक है एस्टेला में शराब पीने के लिए लगा नल। ये वो जगह है, जहाँ पर आपको शराब के तलबगार लोग नल के भर-भर कर कप में शराब पीते नजर आएंगे। बताया जाता है कि एस्टेला शराब के नल का निर्माण साल 1891 में किया गया था। साथ ही ये जगह 12वीं सदी में अंगूरों के बाग के रूप में जानी जाती थी। इसके बाद बदलते वक्त के साथ 1991 में इस जगह को नए तरीके से बनाया गया। यहाँ की छोटी-छोटी शराब की दुकानों की जगह पर शराब के हॉल का निर्माण किया गया, जिसमें रखे 23स्टेनलेस के ड्रमों में कुल लगभग 70 हजार लीटर शराब रखी जा सकती है। ईराक और एस्टेला के वाइन संग्रहालय में आने वाले लोगों के लिए वाइन फाउंडेशन किसी अजूबे से कम नहीं है। यहाँ आने वाले लोगों के लिए शराब परोसने के बेहतर इंतजाम के साथ उनकी मौज-मस्ती के लिए भी खास तैयारियाँ की जाती है।

लेदर स्कर्ट से मिलेगा फॉर्मल और कैजुअल लुक

दिन के वक्त ऑफिस और रात को उसी ड्रेस में पार्टी में जाना चाहती हैं तो लेदर स्कर्ट अच्छा ऑप्शन साबित होगा। शायद एक पल के लिए पार्टी में लेदर स्कर्ट पहनने के बारे में सोच कर थोड़ा असहज जरूर महसूस करेंगी, लेकिन ये एक ऐसा आउटफिट है जिसे कई तरह से स्टाइल किया जा सकता है। लेदर स्कर्ट्स जो कि अभी रेग्य और रेड कारपेट पर छाई हैं, पार्टी और कैजुअल लुक में अच्छे दिखेंगी। जानिए लेदर स्कर्ट पहनने के कुछ तरीकों के बारे में, जिनसे लुक बदलना आसान होगा

पतली कमर की चाह किस स्त्री को नहीं है।

हर उम्र की लड़कियों को पतली कमर की इच्छा होती है। लेकिन दिक्कत यह है कि पतली कमर हासिल करना किसी बड़े टास्क सरीखा हो गया है। पादहस्तासन इसके लिए सबसे सरल और सटीक उपाय है। चूंकि हाथों से पैरों को पकड़कर यह आसन किया जाता है इसलिए इसे पादहस्तासन कहते हैं। यह आसन पेट और कमर के पास जमा फैट को कम करने में मदद करता है जिससे कमर पतली और आकर्षक बनती है। यही नहीं शरीर को लचीलापन भी मिलता है। यही कारण है कि सिर्फ महिलाएं पादहस्तासन का हाथ धरें, यह सही नहीं है। पुरुषों को भी पादहस्तासन अपने पफेक्ट बॉडी शेप के लिए करना चाहिए। इसके बारे में विस्तार से हम आपको बताते हैं।

कैसे करें यह आसन

कंधे और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। अंग दोनों हाथों को धीरे-धीरे ऊपर उठाकर हाथों को कंधे की सीध में लाकर थोड़ा-थोड़ा कंधों को आगे की ओर झुकाते हुए सिर के ऊपर तक उठाएं। ध्यान रहे कि कंधे कानों से सटे हों। हथेलियाँ सामने की ओर हों। जब बाईं-एक-दूसरे के समानांतर ऊपर उठ जाएं तब धीरे-धीरे कमर को सीधा रख सांस अंदर लेते हुए नीचे की ओर झुकना प्रारम्भ करें। झुकते समय भी ख्याल रखें कि कंधे कानों से सटे ही रहें। घुटने सीधे रखते हुए दोनों हथेलियों से एड़ी-पंजे मिले दोनों पाँव को टखने के पास से कस के पकड़कर माथे को घुटने से स्पर्श करने का प्रयास करें। सांस अंदर बाहर करते रहें। सुविधा अनुसार 30-40 सेकंड इस स्थिति में रहें। वापस आने के लिए धीरे-धीरे इस स्थिति से ऊपर उठिए। खड़ी मुद्रा में आकर हाथों को पुनः कमर से सटाने के बाद विश्राम स्थिति में आएँ। 5 से 7 बार ऐसा करें।

इस आसन के फायदे

जैसा कि पहले ही जिक्र किया जा चुका है कि पतली कमर के लिए पादहस्तासन लाभकर है। साथ ही इसके करने से शरीर में लचीलापन भी आता है। इसके अलावा जिन लोगों को अपने कद में वृद्धि करनी है, उनके लिए भी यह सहायक है।

पतली कमर चाहिए तो करें पादहस्तासन

बरतें थोड़ी सावधानी

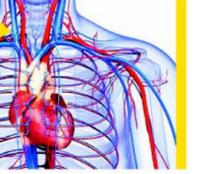
इस आसन को करने से पहले कई प्रकार की सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं। अगर आप अपने पैरों को नहीं छू पा रहे हैं तो इसका आहिस्ता आहिस्ता अभ्यास करें। इसे कर्तई झटपट पूरा करने की कोशिश न करें। पैरों की मांसपेशियों आहत हो सकती हैं। झटके से गर्दन नीचे करने से गर्दन लचक सकती है। इसी तरह की और भी समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। अगर इसे करने की सही विधि से आप बावस्ता नहीं हैं तो बेहतर होगा कि योग विशेषज्ञों से संपर्क करें। इसके अलावा अगर आपमें रीढ़ की हड्डी की किसी भी प्रकार की बीमारी पादहस्तासन करने की इजाजत नहीं देते। अतः इस न करें। साथ हृदय रोगी, उच्च रक्तचाप के मरीजों को भी यह आसन सही नहीं है। उन्हें इसके नुकसान डेलने पर सचेत हैं। एरिडिटी से पीड़ित लोगों के लिए भी यही सलाह दी जाती है कि वे इसे न करें।

हालांकि एक उम्र के बाद कद में वृद्धि असंभव होती है। बावजूद इसके शरीर में खिंचाव होने के कारण कद की सामान्य वृद्धि देखी जा सकती है। बच्चों के लिए यह आसन बेहद फायदेमंद है। खासकर उन बच्चों के लिए जिन्हें अपने कद को लेकर संदेह है।

पादहस्तासन की खूबी की सूची अभी खत्म नहीं हुई है। पुरुष इस आसन को न करने की टोस वजह दे सकते हैं कि यह आसन महिलाओं के लिए कारगर है। जबकि चौड़े सीने की चार रेखाएँ वालों के लिए भी यह पफेक्ट योगासन है। अतः

वयों जरूरी है ब्लड सर्कुलेशन

रक्त मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पूरे शरीर में न्यूरिट्रेंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन्स, डीएनए और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम रक्त ही करता है। शरीर के विभिन्न हिस्सों को स्वस्थ रखने और रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम भी ब्लड ही करता है। रक्त वाहिनियों की शाखाएँ और घुमाव रक्त संचार को बाधित करते हैं और हृदय रोग की वजह बनते हैं।



सी पैप मशीन रातों को देगी सुकून



आपने अपने आसपास कुछ लोगों को सोते समय खरटि लेते हुए देखा होगा, कई बार ये खरटि स्लीप एजिया भी कहते हैं। इसे नाक पर लगाकर सोने से स्टीम मिलती रहती है। जिससे वायु-मार्ग खुला रहता है व व्यक्ति चैन की नींद सो सकता है। इसके इस्तेमाल से खरटों में कमी होने के साथ-साथ नींद पूरी होने व ऑक्सीजन ठीक से मिलने से आप दिनभर एक्टिव रहते हैं, मूड ठीक रहता है व याददाशत में सुधार होता है।

क्या है स्लीप एजिया?

सोते समय जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन नाक या मुँह के माध्यम से गले में स्थित वायु-मार्ग से होती हुई सीधे फेफड़ों और हृदय तक पहुंचती है। लेकिन कुछ लोगों में विभिन्न कारणों की वजह से यह मार्ग बाधित हो जाता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पाती और यह स्थिति गले में कंपन पैदा करती है जो कि खरटों के रूप में सुनाई देती है। कभी-कभी यह रूकावट इतनी गंभीर हो जाती है कि गले का वायु-मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति को बेचैनी महसूस होने लगती है। विशेषज्ञों के मुताबिक खरटों के कारण नींद पूरी नहीं हो पाती जिससे कमजोर एकाग्रता, सुस्ती और उनीदापन जैसे लक्षण होते हैं जो कि आगे चलकर ब्रेन स्ट्रोक और दिल के दौरों का जोखिम बढ़ा सकते हैं। साथ ही इससे लकवा, मानसिक अवसाद व डायबिटीज जैसी बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है।

प्रमुख कारण

मुँह और गले की बनावट, छोटा जबड़ा, लंबी जीभ या अधिक वजन के कारण दोहरी ठोड़ी होना, सिगरेट की लत, मोटापा और लंबे समय तक जुकाम बना रहना।

ऐसे दूर होगी समस्या

सी-पैप मशीन: यह स्लीप एजिया के लिए कारगर उपचार है। इसे नेबोलाइजर भी कहते हैं। इसे नाक पर लगाकर सोने से स्टीम मिलती रहती है। जिससे वायु-मार्ग खुला रहता है व व्यक्ति चैन की नींद सो सकता है। इसके इस्तेमाल से खरटों में कमी होने के साथ-साथ नींद पूरी होने व ऑक्सीजन ठीक से मिलने से आप दिनभर एक्टिव रहते हैं, मूड ठीक रहता है व याददाशत में सुधार होता है। आजकल ये मशीन छोटे आकार व पहले की तुलना में हल्की आने लगी है जिसे रातभर बिस्तर के किनारे रखकर चैन की नींद सो सकते हैं।

सर्जरी भी है विकल्प: यदि आप रोजाना मशीन लगाने से बचना चाहते हैं तो इसका अन्य विकल्प है सर्जरी। यह उन लोगों को लिए भी अच्छा है जिनके मुँह और गले की बनावट में विकृति होती है। सर्जरी में रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन द्वारा श्वास-मार्ग चौड़ा किया जाता है जो कि जबड़े की बनावट या किसी वजह से सिकुड़ गया है।

वजन करंट कंट्रोल: अधिक वजन भी स्लीप एजिया का एक प्रमुख कारण है। ऐसे में वें वें लोग जिनकी वजन मोटी है, उनमें वायु-मार्ग के आसपास अधिक ऊतकों के देबाव की आशंका रहती है। इससे वायु-मार्ग ब्लॉक हो सकता है। ऐसे में वजन कम करना जरूरी है।

औषधीय गुणों का भंडार है सदाबहार

कैंसर ऐसी बीमारी है जिसका पता सामान्यतः रोग बढ़ने के बाद ही चल पाता है। इस स्थिति में सर्जरी ही बीमारी के विकल्प के रूप में सामने आती है। आयुर्वेद शोधकर्ताओं ने सफेद फूल वाले सदाबहार पौधे को इस बीमारी में प्रभावी माना है।

इस तरह हैं कैंसर में लाभकारी

ये पत्तियाँ कैंसररोधी हैं। ये रोग बढ़ाने वाली कोशिकाओं के विकास को रोकती हैं साथ ही इस दौरान क्षतिग्रस्त हो गई कोशिकाओं को फिर से सेहतमंद बनाने का काम करती हैं। यदि इसकी पत्तियों से बने रस को कैंसर की पहली स्टेज वाले मरीज को दिया जाए तो उसके रोग के बढ़ने की आशंका कम हो जाती है। वहीं दूसरी व आखिरी स्टेज के दौरान इसके प्रयोग से मरीज की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होकर उसके जीवित रहने की अवधि बढ़ सकती है।



ध्यान रहे

कड़वा स्वाद होने के कारण इसे खाली पेट लेने से उल्टी हो सकती है। इसलिए इसका प्रयोग कुछ खाकर ही करें। छोटे बच्चों को इसके रस में शक्कर या चूर्ण में गुड़ मिलाकर गोतियों के रूप में दिया जा सकता है।

ब्लड प्रेशर सामान्य करता है श्वासन



यह आसन आरामदायक आसन भी होता है, क्योंकि श्वास का अर्थ है मृत, यानी शरीर श्वास के समान हो जाता है। इसलिए ही इस आसन को श्वासन के नाम से जाना जाता है। यह दो शब्दों के योग से बना है, श्वास+आसन = श्वास आसन या श्वासन। अगर इस आसन को नियमित 15-20 मिनट किया जाए तो दिमाग शांत हो जाता है और उच्च रक्तचाप सामान्य हो जाता है। यह एक स्थिती करने वाला आसन है और शरीर, मन, और आत्मा को ऊर्जा प्रदान करता है। श्वासन एक मात्र ऐसा आसन है, जिसे हर आयुवर्ग के लोग कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि यह आसन किस विधि से किया जाता है और इसके क्या लाभ होते हैं।

कैसे करें श्वासन

इस आसन को करने के लिए पीठ के बल लेटकर दोनों पैरों में ज्यादा से ज्यादा अंतर रखें। पैरों के पंजे बाहर और एड़ियाँ अंदर की तरफ होंनी चाहिए। दोनों हाथों को शरीर से लगभग एक फिट की दूरी पर रखें। हाथों की अंगुलियाँ मुड़ी हुई हों और गर्दन को सीधा रखें, आँखों को भी बंद रखें। श्वासन में सबसे पहले पैर के अंगुठे से लेकर सिर तक का भाग छेड़ा छोड़ दें। पूरा शरीर छेला छोड़ने के बाद सबसे पहले मन को श्वास-प्रश्वास के ऊपर लगाते हैं और मन के द्वारा यह महसूस करते हैं कि दिनों नासिकाओं से श्वास अंदर आ रही है तथा बाहर आ रही है। जब श्वास अंदर जाती है तब नासिका के अग्र में हलकी-सी उठक



महसूस होती है और जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तब हमें गरमाहट महसूस होता है। इस गरमाहट व उठक को अनुभव करें। इस तरह नासाग्रस से क्रमशः सीने तथा नाभि पर ध्यान केंद्रित करें। मन में उल्टी गिनती गिनते जाएँ। 100 से लेकर 1 तक। यदि गलती हो जाए तो फिर से 100 से शुरू करें। ध्यान रहे कि आपका ध्यान सिर्फ शरीर से लगा हुआ होना चाहिए, मन में चल रहे विचारों पर नहीं। इसके लिए सांसों की गहराई को महसूस करें।

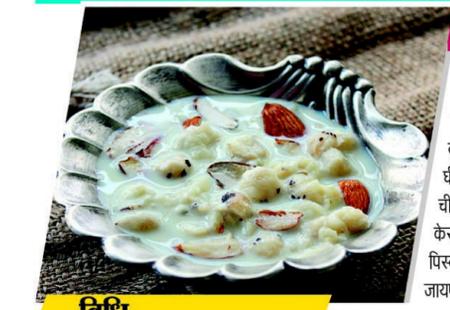
श्वासन के फायदे

इस आसन को नियमित करने से श्वास की स्थिति में हमारा मन शरीर से जुड़ा हुआ रहता है, जिससे शरीर में किसी प्रकार के बाहरी विचार उत्पन्न नहीं होते, यानी नकारात्मक विचार नहीं आते। इस कारण से हमारा मन पूर्णतः आरामदायक स्थिति में होता है, तब शरीर स्वतः ही शांति का अनुभव करता है।

थोड़ी सावधानी भी जरूरी

इस आसन का फायदा तभी है जब इसे करने दौरान आपकी आँखें बंद हों। हाथ को शरीर से एक फिट की दूरी पर व पैरों में एक से डेढ़ फीट की दूरी जरूरी है। इसमें शरीर को ढीला छोड़ देना चाहिए। श्वास की स्थिति में शरीर को हिलाना नहीं चाहिए। यह मानसिक शांति और शुक्ल प्रदान करने वाला आसन है, इसे करने से मन और दिमाग दोनों शांत रहते हैं।

रेसिपी



विधि

कढ़ाई में थोड़ा घी डाल कर गरम कीजिए अब उसमें मखनी डाल कर भून लीजिए। मखनी टंडा होने के बाद मिक्सी से पीस लीजिए। अब एक बर्तन में दूध और चीनी डाल कर उबालते रहें। चाशनी बनने के बाद आंच को धीमी करके मखनी पाउडर डाल कर मिलाए। अब दूध उबाल कर आधा होने के बाद पकाए। उसके बाद केसर, जायफल पाउडर मिलाकर 1 मिनट पकाए। मिश्रण टंडा होने के बाद उसके ऊपर पिस्ता डाल कर सजाए। मखनी की खीर तैयार।



विधि

मैदा में नमक, अजवाइन, तेल डाल कर मिलाए अब उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर नरम आटा गुथ लीजिए। आलू को उबाल कर छिलका हटा कर मेश कर लीजिए प्याज और हरी मिर्च को बारीक काट लीजिए। कढ़ाई में तेल डाल कर गरम कीजिए अब उसमें जीरा और अदरक डाल कर भुने उसके बाद बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च डालकर पकाए अब नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर डाल कर मिलाए उसके बाद मेश किया हुआ आलू डाल कर अच्छी तरह मिलाकर 2 मिनट पका कर गैस बंद कर लीजिए। अब आटे से निम्बू के आकार की लोई तोंडकर गोल कर लीजिए, एक लोई उठाए और हाथ पर रखकर उसे ऊपरियों की सहायता से बड़ा कर, टोकरा जैसा बना लीजिए, आटे की इस टोकरा में आलू मिश्रण 1 या 2 चम्मच डाल दीजिए और आटे को चारों ओर से उठाकर मिश्रण को अच्छी तरह बंद करके कचोरी जैसा बना लीजिए, इसी तरह सारे कचोरी बना लीजिए। अब कढ़ाई में तेल डाल कर गरम कीजिए, अब जितनी कचोरी कढ़ाई में आ जाय उतनी कचोरी कढ़ाई में डाल कर दोनों ओर गोल्डन ब्राउन होने तक तल कर निकाल लीजिए, इसी तरह सारे कचोरी बना कर तैयार कर लीजिए, गरमा गरम आलू की कचोरी तैयार।

मखाने की खीर

सामग्री

- फूल मखनी - 1 कप
- दूध - 5 कप
- घी - 2
- चीनी - 1/4 कप
- केसर - 1
- पिस्ता -
- जायफल पाउडर - 1/2

आलू कचौड़ी

सामग्री

- मैदा - 1 कप, अजवाइन - 1/2, तेल - 2, स्ट्रॉफिंग के लिए, आलू - 3, प्याज - 1, हरी मिर्च - 1, अदरक - (बारीक कटा हुआ), लाल मिर्च पाउडर - 1/2, हल्दी - 1/4
- धनिया पाउडर, जीरा - गरम मसाला पाउडर - 1/2, नमक - स्वादानुसार, तेल - अवयस्कता अनुसार